RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

दुनिया एक जादुई खिलौना है, जो मिल जाए वह मिट्टी और जो न मिले वह सोना है

विकास दिव्यकीर्ति

वर्ष-08, अंक - 23 (साप्ताहिक) खवासा, गुरूवार 19 मार्च 2026 पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

प्रशासन के कागजी घोड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर तो है...!

किसानों का पीएचई ऑफिस के सामने पेयजल के लिए लगातार डटे रहना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

वैसे तो इस देश को आजाद हुए लगभग 8 वां दशक होने को है, लोकतंत्र को वजूद में आए भी लगभग इतना ही समय हो चला है। बावजूद इसके देश के बहुत से हिस्से अब भी ऐसे है जहां मूलभूत सुविधाओं का पूरी तरह से अभाव बना हुआ है। आए दिन यह खबरें देखने और सुनने को मिलती ही रहती है कि, आजादी के इतने सालों बाद भी देश के किसी न किसी हिस्से में पानी, बिजली और सड़क जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। आजादी के इतने समय बाद भी ऐसा क्यों है...? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है या फिर हर किसी के पास है, लेकिन सार्वजनिक नहीं है। यह इस देश की विडम्बना ही कही जाएगी कि, आजादी के इतने दशकों बाद भी तंत्र और सरकारें इस देश के उस अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाई है जिसके नाम से सरकारें हमेंशा अंत्योदय की योजनाएं लाती रहती है। दुनिया आधुनिकता की चकाचैंध की ओर बढ़ रही है और हमारे देश का हाल यह है कि, अब भी यहां दुरूस्त अंचलों में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे है।

इसी कड़ी में इस देश के सबसे पिछड़े और गरीब जिलों की फहरिस्त में आने वाले झाबुआ और आलीराजपुर जिले भी शामिल है। इन जिलों में लोग आए दिन किसी न किसी मूल-भूत सुविधा के लिए जिला मुख्यालय पर धरना देते देखे जा सकते है या फिर कलेक्ट्रोरेट भवन के गलियारों में इन्ही मूलभूत सुविधाओं के लिए अपनी चप्पलें घिसते नजर आते है। अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाते है, अफसरों को सेवा चाकरी का भरोसा भी दिलाते है। मगर विडम्बना देखिए कि, इतना सबकुछ करने के बावजूद भी उनके हथपल्ले सिर्फ अधिकारियों के आश्वासन के झुनझुने ही हाथ लगते है।

झाबुआ जिले में भी एक घटनाक्रम ऐसा ही सामने आकर खड़ा हो गया है। जिसने प्रशासन की कार्यप्रणाली और अंत्योदय तक पहुंचने के प्रशासनिक दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। लगभग आठ दिन पहले जिले के ग्रामीण किसानों ने जल जीवन मिशन में

गड़बड़ी को लेकर राष्ट्रीय किसान संगठन के बेनर तले जिला मुख्यालय पर एक धरना दिया था। आरोप लगाए गए थे कि, जल जीवन मिशन में भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही हो रही है। ग्रामीणों तक इस योजना से हर घर पेयजल नहीं पहुंच पा रहा है। गांवों में टंकिया बनी है लेकिन उसमें कहीं पानी नहीं है, तो कहीं पेयजल पाइप लाईन ही अधूरी पड़ी है, कहीं टंकियां भरने के लिए जल स्त्रोत नहीं है, ऐसी स्थिति में जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनी टंकियां गांवों में महज सजावटी सामान बन कर रह गई है। तो सूखे नलों की टोटियां किसानों को चिढ़ा रही है कि, चलो पानी ना आया तो क्या हुआ नल तो आया। इसमें पानी भी देर सवेर आ ही जाएगा।

प्रशासन ने किसानों के आक्रोश और धरने को देखते हुए जांच दल गठित करने और जिले की 483 पूर्ण योजनाओं में सुधार के लिए 7 दिन का समय मांगा और आश्वासन का झुनझुना किसानों को थमाया कि, 7 दिनों में गांव-गांव, घर-घर जल पहुंच जाएगा। इसके बाद किसानों ने उस समय अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त कर दिया था। मंगलवार को प्रशासन द्वारा दी गई आश्वासन रूपी झुनझुने की 7 दिवसीय मोहलत पूरी हो गई। लेकिन जल जीवन मिशन योजना की स्थिति में रत्तीभर का भी बदलाव देखने को नहीं मिला। किसान इस स्थिति को देखकर आक्रोशित हो गए और जिले भर के किसान मंगलवार को साढ़े 12 बजे से पीएचई कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से स्थिति के बारे में जानकारी चाही। लेकिन अधिकारी किसानों के सवालों का संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सके। इसी दौरान किसानों और पीएचई कार्यालय के अधिकारियों में बहस भी हुई। जिसके बाद किसान यहीं पीएचई कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान तहसीलदार, पीएचई के मुख्य कार्यपालन यंत्री ने किसानों से बातचीत कर मनाने का प्रयास किया, लेकिन किसान अब अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे है। मंगलवार को किसानों का धरना दिनभर जारी रहा तो रात भी किसानों ने पीएचई कार्यालय के सामने ही गुजारी। धरना स्थल पर ही खाना बनाया और खाया गया। बुधवार सुबह से लेकर शाम तक भी किसान अपने धरने पर जमे रहे। इस दौरान पीएचई कार्यालय का मुख्य द्वार बंद ही रहा। कार्यालय में कामकाज और कर्मचारियों की आवाजाही के लिए पिछले रास्ते का इस्तेमाल करते देखे गए।

धरने में शामिल किसानों का कहना है कि, कई गांव ऐसे है जहां पूरी योजना का काम हो चुका है लेकिन गांव के एक भी घर में अब तक पेयजल नहीं पहुंच पाया है। जबकि जिला प्रशासन और उसके अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ाते और वाहवाही लूटते दिखाई देते है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ ओर ही है। गांवों में लोगों को पेयजल के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने सात दिन में व्यवस्था सुधारने का वादा किया था लेकिन अधिकारी अपने वादे पर खरे नहीं उतरे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग सक्षम है वे तो पानी खरीद लेते है लेकिन गरीब किसान या ग्रामीण अब भी पेयजल के लिए भटकता ही नजर आता है। किसान बताते है कि, जो जांच दल बनाया गया था उसे 14 दिनों में जांच पूरी कर जिले के सभी उपखंडों की जांच कलेक्टर को सौंपना है। इस जांच दल में वे अधिकारी भी शामिल है जिन पर हम गड़बड़ी के आरोप लगा रहे है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि, बीते आठ दिनों में इस मामले में एक पत्ता तक नही हिला तो फिर अगले 6 दिनों में जांच टीम के अधिकारी कैसा मीर मारेंगे। उधर प्रशासनिक और पीएचई विभाग के अधिकारियों के अपने ही बोलवचन है। अधिकारी कहीं भी इस बात को गंभीरता से लेते दिखाई नहीं दे रहे है।

यह इस जिले का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि, आजादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी इस जिले के ग्रामीण पेयजल के लिए आंदोलन, प्रदर्शन और धरना व खाली बर्तन बजा रहे है। देश आजाद हुए लगभग 8 दशक होने को है, इस समय में कई सरकारें आई और गई, वर्तमान सरकार भी अमृतकाल मना रही है। लेकिन इस देश की हकीकत तो यही है कि, यहां अब भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान देने वाला कोई दिखाई नही देता। सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि, नेता, राजनेता और प्रशासनिक तंत्र में अधिकारी मानों सिर्फ माथा उतारनी करने के लिए ही बैठे हों। उन्हे गरीब, किसान और आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जैसे कोई लेना-देना ही नहीं हो।

ऐसा नहीं है कि, यह इस तरह का कोई पहला मामला है। इस तरह के मामले अक्सर मीडिया की सुर्खियों में बने रहते है। माही की गूंज अपने कई अंकों में जिले भर से इस तरह की नल-जल योजना में लापरवाही और भ्रष्टाचार की दर्जनों खबरें प्रकाशित कर चुका है। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल-जल योजना, जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं धरातल पर ढाक के तीन पात ही साबित हुई है। गांवों में बड़ी-बड़ी पानी की टंकियां तो खड़ी है लेकिन उनमें पानी नही है वह सिर्फ एक शौपीस बन कर रह गई है। इस बार जिले के ग्रामीणों, किसानों का आक्रोश उन्हे आंदोलन और धरना प्रदर्शन तक ले आया है, जो यह साबित करता है कि, प्रशासन के कागजी घोड़ों और जमीनी हकीकत में अंतर तो है...! वह भी जमीन आसमान का।

हमारे साथ मोहब्बत, लेकिन शादी मोदी के साथ-खड़गे

नई दिल्ली, एजेंसी।

राज्यसभा से बुधवार को कई सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी गई। इस अवसर पर सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, जनसेवा और राजनीति में सक्रिय नेता कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। वे देश सेवा के उत्साह में न तो थकते हैं और न ही पीछे हटते हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का उल्लेख करते हुए खड़गे ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उन्होंने मोहब्बत हमारे साथ की, लेकिन शादी मोदी के साथ कर ली, यह कैसे हुआ उन्हें

समझ नहीं आया। उनके इस कथन पर सदन में मुस्कान का माहौल बन गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य सदस्य भी मुस्कुराते नजर आए।

खड़गे ने कहा कि, वे देवगौड़ा को पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से जानते हैं और उनके साथ लंबे समय तक कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन पुराने संबंध हमेशा बने रहते हैं।

इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ नेता शरद पवार का भी उल्लेख करते हुए उन्हें एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बताया और कहा कि, उनके साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं।

खड़गे ने सदन के संचालन पर भी जोर देते हुए कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सदस्य आज विदा हो रहे हैं, उनमें से कुछ पुनः सदन में लौटेंगें, लेकिन जनजीवन में सक्रिय रहने वाले लोग कभी वास्तव में सेवानिवृत्त नहीं होते।

चार मंजिला इमारत में भीषण आग, कई झुलसे

नई दिल्ली।

पालम क्षेत्र में बुधवार को एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि कई लोग झुलस गए। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में पूरी इमारत धुएं और लपटों से घिर गई।

अग्निशमन विभाग के अनुसार आग बुझाने के लिए 25 वाहन लगाए गए। कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है, हालांकि प्रारंभिक जांच में विद्युत शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार आग लगने के बाद क्षेत्र में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के क्षेत्र को खाली कराया तथा यातायात को नियंत्रित किया।

प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इमारत की सुरक्षा व्यवस्था और आग से बचाव के उपायों की जांच की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। झुलसे हुए लोगों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दर्दनाक हादसा: चार्ज हो रही कार से लगी आग, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

इंदौर।

ग्रेटर बृजेश्वरी कॉलोनी में बुधवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों की जिंदा जलकर मृत्यु हो गई। मृतकों में एक डेढ़ वर्ष का मासूम और महिलाएं भी शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि, सुबह 4 बजे घर के बाहर चार्ज हो रही विद्युत कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग तेजी से घर तक पहुंच गई और वहां रखे प्लास्टिक सामान तथा रासायनिक पदार्थों ने आग को और भड़का दिया। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखे चार गैस सिलेंडर एक के बाद एक धमाके के साथ फट गए, जिससे मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान घर के दरवाजों में लगे स्वचालित ताले बड़ी बाधा बन गए। आग के कारण बिजली आपूर्ति बंद होते ही दरवाजे जाम हो गए और अंदर फंसे लोग बाहर नहीं निकल सके। पड़ोसियों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन आग की तीव्रता के कारण वे अंदर नहीं जा सके। बाद में बचाव दल ने दरवाजे तोड़कर लोगों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

हादसे में विजय सेठिया (65), सुमन (60), मनोज (65), टीनू (35), सिमरन (30), छोटू (22) और राशि (12) की मृत्यु हो गई। घटना के समय घर में पारिवारिक कार्यक्रम के कारण कई सदस्य एकत्रित थे। हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार अस्पताल में जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे और गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, विद्युत वाहनों के बढ़ते उपयोग के बीच यह घटना एक गंभीर चेतावनी है। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञों की टीम बनाकर मामले की जांच की जाए।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 6 यूक्रेनी को पकड़ा, एक अमेरिकी भी हिरासत में

नई दिल्ली, एजेंसी।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 6 यूक्रेनी नागरिकों को हिरासत में लिया है। इन पर अवैध रूप से मिजोरम में प्रवेश करने और फिर पड़ोसी देश म्यांमार जाकर उग्रवादी समूहों को लड़ाई का प्रशिक्षण देने का आरोप है। एजेंसी ने दिल्ली और लखनऊ सहित विभिन्न आवागमन केंद्रों से इन नागरिकों को पकड़ा है। इसके अलावा एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को कोलकाता हवाई अड्डे से हिरासत में लिया गया है। सभी के विरुद्ध गैरकानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जांच एजेंसियों के अनुसार ये विदेशी नागरिक मिजोरम पहुंचे थे, जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य माना जाता है और म्यांमार के साथ लगभग 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इस क्षेत्र में विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए विशेष अनुमति अनिवार्य होती है, लेकिन आरोप है कि इन लोगों ने बिना अनुमति के प्रवेश किया।

एजेंसियों का यह भी कहना है कि इन नागरिकों ने म्यांमार में सक्रिय कुछ जातीय सशस्त्र समूहों से संपर्क कर उन्हें प्रशिक्षण और उपकरण उपलब्ध कराए। पकड़े गए सभी लोग ड्रोन तकनीक में दक्ष बताए जा रहे हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार ये लोग उग्रवादी समूहों को ड्रोन आधारित युद्धक तकनीक सिखाने के उद्देश्य से पहुंचे थे, जिससे भारत के मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड जैसे सीमावर्ती राज्यों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।

इस मामले पर यूक्रेन ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ओलेक्सैंडर पोलिशचक ने विदेश मंत्रालय को औपचारिक विरोध पत्र सौंपा है। यूक्रेन का कहना है कि उसके नागरिकों के खिलाफ अभी तक किसी भी आपराधिक गतिविधि के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं।

यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि, हिरासत में लिए गए नागरिकों की जानकारी समय पर नहीं दी गई, जो वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संधि के अनुसार किसी भी विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी या हिरासत की स्थिति में उसके देश के दूतावास को तुरंत सूचित करना आवश्यक होता है।

इस बीच 16 मार्च को दिल्ली की एक अदालत में सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों की हिरासत 27 मार्च तक बढ़ा दी गई। सुनवाई के समय यूक्रेनी दूतावास के अधिकारी उपस्थित थे, लेकिन उन्हें हिरासत में लिए गए लोगों से सीधे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, जिस पर यूक्रेन ने आपत्ति जताई है।

वहीं अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक के मामले में अमेरिका ने सतर्क रुख अपनाया है। अमेरिकी दूतावास ने जानकारी होने की पुष्टि की है, लेकिन गोपनीयता के कारण विस्तृत टिप्पणी से इंकार किया है।

सेवानिवृत्त अधिकारी को डिजिटल गिरफ्त में रखकर 1.05 करोड़ रुपए ठगे

मुंबई।

दादर क्षेत्र में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक सेवानिवृत्त अधिकारी को 10 दिनों तक डिजिटल माध्यम से बंधक बनाकर 1.05 करोड़ रुपये की ठगी की गई। पीड़ित श्रेयष परलकर (71) को ठगों ने खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर डर और मानसिक दबाव में रखकर ठगी को अंजाम दिया।

पीड़ित के अनुसार 4 मार्च को उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के दिल्ली मुख्यालय का अधिकारी बताया और कहा कि उनके आधार कार्ड का उपयोग कर एक नया मोबाइल नंबर जारी किया गया है, जिसका इस्तेमाल अवैध संदेश और उत्पीड़न के लिए हो रहा है। इसके बाद कॉल को कथित जांच एजेंसी के अधिकारियों से जोड़ दिया गया।

अलग-अलग व्यक्तियों ने स्वयं को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पीड़ित को धन शोधन के मामले में फंसाने और गिरफ्तारी की धमकी दी। ठगों ने विश्वास दिलाने के लिए न्यायालय के आदेश, गिरफ्तारी वारंट और सरकारी पत्र जैसे दस्तावेज संदेश माध्यम के जरिए भेजे।

ठगों ने पीड़ित को यह कहकर डिजिटल रूप से बंधक बनाए रखा कि वे जांच के दायरे में हैं और किसी से संपर्क नहीं कर सकते। उन्हें एक संवाद अनुप्रयोग डाउनलोड कराकर हर दो घंटे में अपनी स्थिति की जानकारी देने को कहा गया। इस दौरान उन्हें लगातार डराया गया और सहयोग न करने पर गिरफ्तारी की धमकी दी गई।

ठगों ने पीड़ित से उनके बैंक खातों, निवेश और बचत से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त कर ली और धन सत्यापन के नाम पर विभिन्न खातों में राशि स्थानांतरित करने के लिए मजबूर किया। 6 मार्च से 12 मार्च के बीच पीड़ित ने चार अलग-अलग लेन-देन में कुल 1.05 करोड़ रुपये भेज दिए।

15 मार्च को पीड़ित के पुत्र ने उनका मोबाइल जांचा, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद तत्काल साइबर सहायता संख्या 1930 पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों और संबंधित बैंक खाताधारकों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिपोर्ट - चितारू ईरान के चाबहार बंदरगाह परियोजना पर संकट के बादल

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया क्षेत्र में ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना को लेकर चिंता जताई गई है। यह मुद्दा विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट में सामने आया, जिसे मंगलवार को संसद में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया घटनाक्रम के कारण बंदरगाह विकास की यह परियोजना खतरे में पड़ सकती है।

चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधा संपर्क स्थापित करने में सहायता मिलती है। साथ ही यह बंदरगाह अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे से जुड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय संघर्ष, अमेरिका द्वारा पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध तथा शुल्क संबंधी निर्णयों का इस परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। समिति ने सरकार द्वारा सभी संबंधित पक्षों के साथ संवाद बनाए रखने के प्रयासों का स्वागत किया है और इस प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता बताई है।

समिति की यह 12वीं रिपोर्ट वर्ष 2026-27 की अनुदान मांगों से संबंधित है, जिसे 17 मार्च को संसद में प्रस्तुत किया गया। समिति की अध्यक्षता वरिष्ठ सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। समिति ने मंत्रालय से परियोजना से जुड़ी योजनाओं और प्रगति की जानकारी नियमित रूप से साझा करने के लिए भी कहा है।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जिसे संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये कर दिया गया था। यह राशि जनवरी 2026 तक पूरी तरह व्यय कर ली गई।

हालांकि, वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस परियोजना के लिए कोई नई राशि निर्धारित नहीं की गई है। मंत्रालय के अनुसार भारत अपनी 120 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता पहले ही पूरी कर चुका है, जिसमें बंदरगाह के लिए उपकरणों की खरीद शामिल है। यह व्यवस्था दोनों देशों के बीच वर्ष 2024 में हुए समझौते का हिस्सा है।

प्रस्फुटन शक्ति संचय प्रशिक्षण संपन्न

माही की गूंज, काकनवानी।

मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड थांदला द्वारा चयनित ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का क्षमतावर्धन प्रस्फुटन शक्ति संचय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत काकनवानी में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को मजबूत करना तथा समितियों को सशक्त बनाना।

मुख्य अतिथि संभाग समन्वयक अमित शाह इंदौर, सामाजिक कार्यकर्ता सरपंच प्रतिनिधि बाबू निनामा, जिला समन्वयक प्रेमसिंह चैहान, ब्लॉक समन्वयक वर्षा डोडियार उपस्थित रहे। अमित शाह ने कहा कि, प्रस्फुटन समितियो के प्रशिक्षण से निश्चित ही आपके कार्य में दक्षता आएगी। शासन की विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। अपने-अपने ग्राम को आदर्श बनाने की दिशा में कार्य करे।

सरपंच प्रतिनिधि ने अपने उद्बोधन में कहा कि, गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है। उन्होंने ग्राम विकास के नौ महत्वपूर्ण मंत्र बताते हुए ग्रामीणों को छोटे-छोटे प्रयासों से गांव को आदर्श बनाने का आह्वान किया। जिला समन्वयक प्रेमसिंह चैहान ने प्रशिक्षण का महत्व बताया। जन अभियान परिषद प्रदेश भर में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ग्राम विकास की नई चेतना जगाने का कार्य कर रही है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्फुटन समितियों को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। मेंटर गंगाराम निनामा,राकेश चरपोटा, विनीता मनसारे ग्राम विकास की अवधारणा को विस्तार पूर्वक बताया। साथ में स्वैच्छिक संगठनों का गठन एवं प्रबंधन तथा प्रस्फुटन समितियों के दस्तावेजीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। सीएम सोशल इंटर्नशिप से अमरसिंह कटारा ने ग्राम स्तर तक पहुंचाने की जानकारी दी।

अध्यक्ष संजय भंडारी व सचिव कीर्तिश चाणोदिया हुए नियुक्त

माही की गूंज, पेटलावद।

सकल जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था महावीर समिति की एक आवश्यक बैठक विगत दिनों गुरु मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं समाजजन उपस्थित रहे। बैठक में सर्वसम्मति से संजय भंडारी (गुड्डू) को महावीर समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उनके अध्यक्ष बनने पर उपस्थित समाजजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। नव मनोनीत अध्यक्ष संजय भंडारी ने अपने दो वर्षीय कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें कीर्तिश चाणोदिया को सचिव, अनोखीलाल लोढ़ा एवं विनोद बम को उपाध्यक्ष, अनुपम भंडारी को कोषाध्यक्ष तथा पीयूष पटवा को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई।

बैठक के दौरान पूर्व अध्यक्ष संजय वोहरा ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की जानकारी समाजजनों के समक्ष रखते हुए सभी के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों ने नव नियुक्त अध्यक्ष एवं नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि, समिति समाजहित, धार्मिक एवं सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तथा समाज के विकास के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगी।

एचपीवी वैक्सीन की समीक्षा

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर की अध्यक्षता में एचपीवी वैक्सीन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में समस्त बीएमओ, बीसीएम एवं बीपीएम गूगल मीट के माध्यम से जुड़े।

कलेक्टर द्वारा ब्लॉक वार एचपीवी वैक्सीनेशन की विस्तृत समीक्षा की गई। पेटलावद में वैक्सीनेशन की कम प्रगति होने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। समस्त बीएमओ को निर्देशित किया कि, वैक्सीनेशन हेतु एक दिन पूर्व सूची बनाकर पात्र बालिकाओं को सूचित करे एवं वैक्सीनेशन हेतु प्रेरित करे। कलेक्टर द्वारा वैक्सीनेशन के लिए स्पेशल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये। जिसमें एसडीएम से समन्वय कर निजी शिक्षण संस्थानों के सहयोग से स्कूल बसों के माध्यम से बालिकाओं को वैक्सीनेशन स्थल पर लाया जाए।

वर्तमान में शिक्षण संस्थानों में अवकाश होने से वैक्सीनेशन प्रभावित ना हो अतः आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम के माध्यम से वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के निर्देश दिये। साथ ही बीएमओ, बीसीएम एवं बीपीएम के साथ समन्वय कर माइक्रो मैनेजमेंट कर प्रगति बढ़ाएं एवं एचपीवी वैक्सीनेशन के संबंध में फील्ड में जनजागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिये गये।

लोक सेवा गारंटी व सीएम हेल्पलाइन निराकरण प्रशिक्षण आयोजित

माही की गूंज, झाबुआ।

वर्ष 2025-26 के अंतर्गत लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010, समाधान एक दिवस सेवा, सीएम हेल्पलाइन एवं सीपीग्राम शिकायतों के प्रभावी निराकरण हेतु 17-18 मार्च को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले में पदस्थ लेवल-1 अधिकारियों, ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के पदविहित अधिकारियों एवं सीएम हेल्पलाइन के लेवल-1 अधिकारियों सहित कुल 54 अधिकारियों को 17 एवं 18 मार्च 2026 को कलेक्टर कार्यालय स्थित ई-दक्ष केंद्र में जिला लोक सेवा प्रबंधक श्री संत कुमार चैबे द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन निराकरण, अपीलीय प्रकरणों के निपटान,

ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित तकनीकी समस्याओं के समाधान, सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत शिकायतों के निराकरण, प्रोफाइल प्रबंधन, संतुष्टिपूर्ण निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश एवं शासन के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, निम्न गुणवत्ता वाले निराकरण, 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों, नॉट अटेंडेड शिकायतों तथा सीपीग्राम की लंबित शिकायतों के प्रभावी निराकरण एवं आवश्यक मूलभूत प्रक्रियाओं के संबंध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए ई-टेंडर आमंत्रित

माही की गूंज, झाबुआ।

वर्ष 2026-27 में निष्पादन के चतुर्थ चरण से शेष रही 26 मदिरा दुकानों के 10 समूहों का निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ऑन लाईन ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन किया जाना है।

ऑनलाइन टेण्डर प्रपत्र डाउन लोड एवं ऑफर सबमिट करने की तिथि 18 मार्च 2026 को प्रातः 10.00 बजे से 19 मार्च 2026 को दोपहर 04.00 बजे तक निर्धारित है।

वर्तमान अनुज्ञप्तिधारी अथवा पूर्व वर्ष में कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉडयूल पर पंजीकरण कर चुके आवेदकों को पुनः वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

इच्छुक आवेदकों द्वारा ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निष्पादन की प्रक्रिया, शर्तें एवं निर्बन्धन एनआईसी के पोर्टल एवं मध्यप्रदेश आबकारी विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड की जा सकती है।

विदाई भाषण मे दिग्विजय सिंह ने बताया 'फ्यूचर प्लान'

भोपाल।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुधवार की सदन से सेवानिवृत्त हो गए। अपने विदाई भाषण में उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए सभी से सद्भाव की अपील की। इस दौरान उन्होंने इशारों में अपना फ्यूचर प्लान भी बताया।

उन्होंने कहा कि - मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की वह बात याद आती है-'मैं न थका हूं, न सेवानिवृत्त हुआ हूं। (न मैं टायर्ड हूं, न रिटायर्ड हूं)' आगे चल कर हम और भी काम करेंगे।

माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अब मध्य प्रदेश में वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए अभी से पार्टी के लिए मेहनत करेंगे। उनके बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं।

मैंने हमेशा विचारधारा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया -सिंह

इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि, लोगों को इस बात का आश्चर्य होगा कि मेरे छात्र जीवन में मेरा राजनीति से कभी कोई संपर्क या समर्थन नहीं रहा। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनीं कि मैं 22 वर्ष की आयु में नगर पालिका अध्यक्ष बन गया। सर्वसम्मति से 30 वर्ष की आयु में विधायक चुना गया, 33 वर्ष की आयु में राज्य का मंत्री बना, सांसद बना और 40 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बन गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि, लेकिन मैंने हमेशा अपनी विचारधारा के मार्ग पर चलने का प्रयास किया है। मैंने अपनी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं किया। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने किसी के प्रति कटुता नहीं पाली। मतभेद होते रहे, और विचारधारा में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद होने का अवसर मैंने कभी नहीं दिया।

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने कहा कि, आज भी मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं। हो सकता है कि मेरे भाषण में कई बार कुछ कटुता आ गई हो और किसी को बुरा लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मैं आपको यह अवश्य विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे मध्य प्रदेश विधानसभा हो, लोकसभा हो या यह सदन- मेरे संबंध उन लोगों के साथ भी हमेशा अच्छे रहे हैं, जिनकी विचारधारा से मैं सहमत नहीं था, न हूं और न ही कभी रहूंगा. जहां तक हमारे कॉमरेड्स का प्रश्न है, कार्य संचालन को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन गरीबों के पक्ष में उनकी जो विचारधारा रही है, उसका मैंने हमेशा समर्थन किया है।

मैं व्यवधानों के पक्ष में कभी नहीं रहा- दिग्विजय

उन्होंने कहा कि मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैं उस लोकसभा का सदस्य रहा, जिसमें अटल बिहार वाजपेयी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) और राजीव गांधी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) जैसे नेता रहे। इंदिरा गांधी (तत्कालीन प्रधानमंत्री) ने मुझे कांग्रेस में प्रवेश दिलाया और चंद्रशेखर (तत्कालीन प्रधानमंत्री) भी उस समय संसद में थे। इन सभी महान नेताओं से प्रभावित होकर ही मैंने अपना राजनीतिक सफर तय किया है। मैं सदन में होने वाले व्यवधानों के पक्ष में कभी नहीं रहा। लोकतंत्र की बुनियाद चर्चा है, और सदन में यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वह विपक्ष के साथ संवाद करके कोई समाधान निकाले।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस सदन में अंसारी साहब (पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी) अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने कभी भी बिना पर्याप्त चर्चा के किसी बिल को पारित होने का अवसर नहीं दिया। रास्ता हमेशा संवाद से निकलता है, निकल सकता है और निकलना चाहिए। यही लोकतंत्र की मूल भावना है, जिसमें आज कुछ कमी दिखाई देती है।

'मैं कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं कि...'

सांसद ने कहा कि, मैं आपसे यह भी क5हना चाहता हूं कि आज देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक व्कटुता और मनमुटाव बढ़ रहा है, वह देश के लिए उचित नहीं है। यह न हमारे संस्कारों और संस्कृति के अनुरूप है, न लोकतंत्र के लिए और न ही भारतीय संविधान की भावना के अनुकूल है। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में अपना मार्ग स्वयं तय किया है और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी का आभारी हूं, जिसने मुझे हर सदन में सेवा करने का अवसर दिया।

उन्होंने कहा कि, आज इस अवसर पर मैं उन सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मैं उसी भावना के साथ कार्य करता रहूंगा, जैसा कबीर ने कहा है- 'कबीरा खड़ा बाज़ार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर।'

एक दिवसीय प्रशिक्षण

माही की गूंज, करवड़।

जनभागीदारी को नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से पंचायत भवन करवड़ में 'प्रस्फुटन समितियों' के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में नवांकुर संस्था ''प्रगति समाजिक सेवा समिति'' ने समितियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग किया।जन अभियान परिषद के विकासखंड समन्वयक प्रवीण पंवार ने मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का परिचय, संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों के कार्य और अपेक्षाओं पर विस्तृत जानकारी दी। कृषि विभाग से राजेश पाटीदार द्वारा जैविक खेती के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण मे नवांकुर संस्था के अध्यक्ष वकील वसुनिया के द्वारा समग्र ग्राम विकास की अवधारणा के बारे मे बताते हुए कहा की विकास की शुरुआत पहले स्वयं के बदलाव से होंगी हमें सबसे पहले स्वैच्छिकता के भाव अपने अंदर जगाना होंगे तभी हम गांव के विकास के बारे मे प्रयास करेंगे।

मेंटर देवचंद्र चारेल द्वारा म.प्र. जन अभियान परिषद की परिकल्पना, स्वैच्छिकता, सामुदायिकता एवं स्वावलंबन और समितियों के दस्तावेजकरण के बारे मे जानकारी दी। ग

स्वैच्छिक संगठन के सत्र में सेक्टर प्रभारी राजू सोलंकी ने बताया कि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) किस प्रकार गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और समाज के पिछड़े एवं वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वैच्छिक संगठनों का कार्यक्षेत्र देश-विदेश तक फैला हुआ है और समाज के विकास के लिए सक्रिय सहभागिता की आवश्यकता है। सेक्टर के समिति सदस्य, नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि, नवांकुर सखी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु शिविर

माही की गूंज,झाबुआ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेघनगर में शिविर का आयोजन कर 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के हितग्राही की जाँच की गई। दिव्यांगजनो को पात्रतानुसार नवीन विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदाय एवं नवीनीकरण करने हेतु शिविर का आयोजन सीएचसी मेघनगर पर किया गया। जहा जिले से विशेषज्ञो की गठित टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों के 5 दिव्यांगता प्रमाण जारी किये गए।

अजब एमपी की गजब पुलिसः बेगुनाह से ही गुनेहगार नहीं बनाने के नाम पर 50 हजार की रिश्वत मांगी

मामलाः एक वर्ष पूर्व आत्महत्या के मामले में ज्वेलर्स व्यापारी को रिश्वत नहीं देने पर अपराधी बनाने की धमकी

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

बड़वानी। अजब एमपी की गजब पुलिस की कारस्तानियां माही की गूंज कई बार मय प्रमाण के प्रकाशित कर चुका है। एमपी की पुलिस की कारस्तानियां ऐसी की जीवित व्यक्ति को मृत व मृत व्यक्ति को जीवित बता देती है। इतना ही नहीं पूर्व से मृत व्यक्ति को हत्या जैसे मामले में मुख्य आरोपी तक बना देती है। इस प्रकार की पुलिस की कारस्तानियो के साथ एमपी पुलिस बेगुनेहगार को गुनेहगार बना देती है और असल गुनेहगार को बेगुनेहगार भी बना देती है।

उक्त पुलिस की मनमानी के बदले मोटी रिश्वत ली जाती है। इन्हीं कारस्तानियो के साथ एक और मामला बड़वानी जिले में एमपी की पुलिस की कारस्तानी सामने आई। जिसमें एक ज्वेलर्स व्यापारी को पुराने आत्महत्या के मामले में रिश्वत नहीं देने पर व्यापारी को अपराधी बना देने की धमकी दी गई और रिश्वत की मांग की गई।

9 मार्च सोमवार को इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद सामने आया कि, बड़वानी जिले के अंजड़ थाने में पदस्थ एएसआई महावीर सिंह चंदेल, एक वर्ष पूर्व भारत बर्फा की आत्महत्या के मामले में जांच अधिकारी थे। वहीं उक्त आत्महत्या मामले में अंजड़ निवासी एवं डायमंड ज्वेलर्स संचालक जयराम पिता भगवानसिंह चैधरी को भारत बर्फा आत्महत्या के मामले में जांच के नाम पर थाने पर बुलवाया। तथा थाने पर जांचकर्ता अधिकारी एएसआई महावीरसिंह चंदेल एवं उनके अधीन कार्यरत पुलिसकर्मी आरक्षक पवन प्रजापति ने रिश्वत की मांग की और व्यापारी को धमकाया की 50 हज़ार रुपए की रिश्वत देने पर भारत बर्फा की आत्महत्या का मामला बंद कर देंगे। और अगर रिश्वत नहीं दी तो जयराम चैधरी को मामले में अपराधी बना दिया जाएगा।

चूंकि ज्वेलर्स व्यापारी मामले में पूरी तरह से बेगुनाह था तथा पुलिस के रिश्वत मांगने की कास्तानी व रिश्वत नहीं देने पर उसे जबरन अपराधी बनाने की पुलिस की धमकी एवं रिश्वत की मांग का मय प्रूफ रिकॉर्डिंग के साथ इंदौर लोकायुक्त को शिकायत की गई। जिसके बाद इंदौर लोकायुक्त ने प्रमाण के आधार पर रिश्वतखोर एएसआई महावीरसिंह चंदेल की पुष्टि की। जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने फरियादी जयराम चैधरी को केमिकल युक्त रिश्वत की प्रथम किस्त अनुरूप 15 हज़ार रुपए दिए। जब

कार्यवाही करते हुए लोकायुक्त पुलिस।

रिश्वतखोर एएसआई महावीर सिंह चंदेल, आरक्षक पवन प्रजापति।

जयराम चैधरी ने रिश्वत की राशि आरक्षक पवन प्रजापति के हाथों में दी तथा उक्त रिश्वत की राशि एएसआई तक पहुंची लोकायुक्त पुलिस ने रेकी कर दोनों भ्रष्ट रिश्वतखोर एएसआई महावीरसिंह चंदेल एवं आरक्षक पवन प्रजापति को रंगे हाथ पकडा। एवं उनके हाथ धुलवाने पर केमिकल वाला कलर निकला।

इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने मामले में पंचनामा बनाकर कार्यवाही की, जिसमें एएसआई महावीरसिंह चंदेल ने आरक्षक पवन प्रजापति के माध्यम से मांगी गई 50 हज़ार की रिश्वत में 15 हज़ार रुपए की प्रथम किस्त की राशि रिश्वत लेते हुए पकड़ा। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की धारा 7, बीएनएस 2023 की धारा 61/2 में मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के उक्त रिश्वत लेने के खुलासे के साथ एक और मामला अजब पुलिस की गजब कारस्तानी भी सामने आई जिसमें बेगुनेहगार को रिश्वत नहीं मिलने पर गुनेहगार बना दिया जाता।

सारंगी-रायपुरिया मार्ग हुआ बदहाल गड्ढों से राहगीर हो रहे परेशान

माही की गूंज, सारंगी। संजय उपाध्याय

सारंगी-रायपुरिया के बीच सड़क मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। इस एकल लेन मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्?ढे हो गए हैं, जिससे प्रतिदिन हजारों राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 15 किलोमीटर का यह हिस्सा दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, कई स्थानों पर सड़क का डामर पूरी तरह उखड़ चुका है।

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाला सारंगी-रायपुरिया मार्ग दिन-प्रतिदिन जर्जर होता जा रहा है। गुजरात, उज्जैन, इंदौर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आवागमन के लिए यह प्रमुख संपर्क मार्ग है। किंतु वर्तमान में यह अपने चैड़ीकरण और नवनिर्माण की बाट जो रहा है। एकल लेन मार्ग पर बढ़ते यातायात के दबाव के बीच वाहन चालकों को जोखिम उठाकर आवा गमन करना पड़ रहा है। मार्ग स्वीकृत हो चुका है लेकिन अब तक मार्ग के निर्माण की प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।

ओवरलोड वाहनों से बढ़ी समस्या

साइड पट्टियों की खराब हालत के कारण कई स्थानों पर वाहन सड़क से नीचे उतारना संभव नहीं होता। दो चैपहिया वाहनों की क्रॉसिंग के दौरान अत्यधिक दिक्कत होती है, जिससे विवाद की स्थिति भी बनती है। मार्ग पर पूर्व में कई भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आमजन को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है।

पूर्व जनपद उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह राठौर ने कहा, क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के इंतजार में है...? आम पब्लिक की सुविधा को देखते हुए इस रोड का काम जल्द से जल्द चालू करवाना चाहिए।

कई स्थानों पर होगी घट स्थापना, होगें विविध धार्मिक कार्यक्रम

माही की गूंज ,पेटलावद।

आज घट स्थापना के साथ ही चैती नवरात्रि कि शुरुवात होगी , जगह जगह माता जी प्रांगणों में स्थापना के बाद आने वाले 09 दिनों तक विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मेवानगर पेटलावद स्थित श्री नाकोड़ा पाश्र्व भैरव दरबार परिसर में चैत्र नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री नाकोड़ा पाश्र्वनाथ भगवान, श्री नाकोड़ा भैरव देव एवं श्री नाकोड़ा काला भैरव की असीम कृपा से भैरव के परम उपासक गादीपति सुमित पिपाड़ा के आदर्श अनुसार इस धार्मिक आयोजन का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में क्षेत्र के समस्त सकल श्री संघ को सादर आमंत्रित किया गया है। महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को माताजी की स्थापना के साथ नवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसके बाद 22 मार्च 2026, रविवार को नवरात्रि के विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ट्रस्टी मनीष कुमट,राजेश काठेड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि, कार्यक्रम के तहत 26 मार्च 2026, गुरुवार को सुबह 8 बजे भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा, जिसमें 9 अश्व, 9 बग्गियां, बैंड-बाजे, 11 ढोल और ध्वज के साथ विशाल शोभायात्रा निकलेगी। वहीं 27 मार्च 2026, शुक्रवार को सुबह 9 बजे विधि-विधान के साथ 9 कुंडीय हवन एवं पूर्णाहुति कर श्री अछूता माताजी की प्रतिष्ठा की जाएगी। आयोजकों के अनुसार यह मेवानगर पेटलावद में श्री अछूता माताजी की प्रतिमा स्थापना का विशेष धार्मिक अवसर रहेगा। जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है।

बिजली विभाग की लापरवाही कभी किसी की जान ले सकती है...

माही की गूंज, खवासा/भामल। सुनिल सोलंकी

खवासा विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत आने वाले रन्नी फिटर के भामल गांव मे हाई स्कूल के नजदीक एक ट्रांसफॉर्म का स्टैंड बनाकर ट्रांसफॉर्म लगा रखा है। लेकिन स्टैंड तो एक है लेकिन दो ट्रांसफॉर्म वहां एक साथ लगा रखे हैं। तो वहीं जहां तार नीचे हैं, उन पर जोर-जुगाड़ करके पत्थर से तार को नीचे लटका कर बाद रंखे ताकि कोई भी तार आपस में टच ना हो। लेकिन यह लापरवाही कभी किसी की जान ले सकती है। ज्ञात हो कि, विद्युत वितरण केंद्र प्रति वर्ष मेंटेनेंस के नाम पर अघोशित कटौती तो करता है, लेकिन मेंटेनेंस कहां करता है यह लापरवाही देखना है, तो भामल के ट्रांसफॉर्म में देख सकते हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भामल गांव में वोल्टेज की काफी समस्या रहती थी इसके समाचार भी हमने प्रमुखता से लिखे थे। उसके बाद विभागीय अधिकारियों की नींद खुली और भामल में तीन नए ट्रांसफॉर्म सौ-सौ वाट के लगाने के इस्टीमेन्ट बनाए गए। लेकिन यहां पुराने ढरै पर ही ट्रांसफॉर्म लगा दिए।

जबकि इनका नए सिरे से सभी जगह नए स्टैंड बनाने के साथ सभी डीपी पर व्यवस्थित लाइट सुचारू रूप से चालू करने का प्रावधान था। लेकिन यहां विद्युत विभाग के अधिकारी व ठेकेदार मिलकर स्टीमेंट के अनुसार कार्य नही करते हुए मामले में लीपापोती कर दी गई। जिससे कहीं ना कहीं विभाग की साख पर भी भट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है।

ग्रामीणों का कहना है कि, जब सभी जगह तीनों नए ट्रांसफॉर्म स्टैंड बनाने के साथ नए लगने थे। तो उन्होंने जोर-जुगाड़ करके पुराने ट्रांसफॉर्म क्यों लगाए...? जबकी इनको नए सिरे से सभी जगह व्यवस्थित ट्रांसफार्म लगाकर लाइट का संचालन करना था।

यहां तो यह प्रतीत होता है कि, ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों की मिली-भगत करके भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वही जिले एवं संभागीय अधिकारी अगर जांच करें तो निश्चय ही अधिकारी, कार्रवाई के लपेटे में आ सकते हैं या इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन यहां कौन, किसकी सुनता है, विभाग तो अपने मनमानी करने पर उतारू है, और यहां ग्रामीणों की कभी भी जान जोखिम में डाल सकते हैं। क्योंकि आसपास स्कूल के समय बच्चों के साथ ही खेत पर मजदूर भी कार्य करने पहुंचते हैं। तो वहीं अधिकारियों ने एक ही स्टैंड पर दो ट्रांसफॉर्म लगा दिए। लेकिन जो पुराना ट्रांसफॉर्म है उसको उतारा ही नहीं और नया ट्रांसफॉर्म लगाकर इति श्री की गईं। जिससे कहीं ना कहीं ठेकेदार व विभागीय अधिकारियों के मिली भगत साफ दिखाई दे रही है।

सृष्टि के नौ चरण, छः ऋतुओं की अभिव्यक्ति है हिंदू नववर्ष

माही की गूंज, झाबुआ। रिंकेश बैरागी

भारतीय उत्सव, पर्व, और त्योहार वैज्ञानिक संस्कृति, सभ्यता में सुदृढ़ सदाचार के साथ-साथ संस्कृति के प्रत्येक क्रम में ज्ञान-विज्ञान का उपक्रम व्यक्ति के बौद्धिक स्तर को नभ की नीलिमा से भी अधिक ऊंचाई पर ले जाता है। हिंदू नव वर्ष ऐसे ही वैज्ञीनिक दृष्टिकोण को स्वयं में समाये हुए सृष्टि के आरंभ का स्वरुप है। जिसमें नवीनता का पल्लव, और जीवन क्रम की वर्षभर में अनुभूति है। भारतीय सुदृढ़ सभ्यता की संस्कृति के समस्त पर्व और त्योहारों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाया हुआ है। हिंदू नववर्ष या चैत्र नवरात्र हमारी सृष्टि के सृजन और आरंभ का प्रतीक है। प्रकृति प्रतिपदा पर स्वरुप में बदलाव करती है, और खिलखिलाती हुई दिखाई देती है। आनंदमयी प्रकृति में इस दौरान पेड़, पौधौ में पल्लव होता है, फूलों से खिली धरा सौंदर्या स्वरुप नव जीवन को जन्म देती है।

पृथ्वी की परिक्रमा के फलस्वरुप प्रकृति में छः ऋतुएं होती है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, और वसंत ये ऋतुएं प्रकृति पर अपने अलग प्रभाव का सामर्थ्य रखती है। सनातन हिंदु वर्ष ऋतुओं में क्रमबद्ध जीवन चक्र को समझाता, जिसकी शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से होती है। कैसे ग्रीष्म ऋतु में संचार होता है और फिर वर्षा ऋतु में पल्लव और भोजन के बाद शरद ऋतु में कलाओं के उत्साह के साथ महालक्ष्मी का जन्म, और हेमंत में बसाहट के साथ शिशिर ऋतु में ठंड से सब स्थिर हो जाता है। जिसके पश्चात वसंत ऋतु में रस की उत्पत्ति, और मदनोत्सव के साथ युग्म बनाकर प्रकृति का संचार, और फिर से नव जीवन प्रारंभ होता है।

सृष्टि सृजन की ओर जायें तब, सर्वप्रथम सब कुछ शुन्य था, पूर्ण ब्रह्म। उस काल में शिव शक्ति शुन्य थे, जाग्रत और चैतन्य थे इसलिये वे किसी आकार या आकृति के स्वरुप में नहीं थे। शक्ति पूर्णरुपेण शिव में समाई थी, अर्थात वह गति में नहीं थी।

आत्म-स्वतंत्रता बोध से सृजन की इच्छा को लेकर जब शक्ति, शिव से प्रथक होकर दूर हुई। शक्ति और शिव शुन्य से दो हो गये। दूर हो जाने पर शक्ति और शिव में परस्पर आकर्षण पैदा हुआ। आकर्षण से शिव और शक्ति के मध्य काम का जन्म होता है, जिसके बाद शिव और शक्ति के युग्म से बिंदु या अण्ड का निर्माण होता है। शक्ति अपने अण्ड या बिंदु में स्वयं का संचार करती है और फिर उस बिंदु में महा विस्फोट होता है जिसके कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह समय माह चैत्र शुक्ल पक्ष का कहलाया, जहां से जीवन की शुरुआत हुई। यह चैत्र मास सृष्टि के आरंभ का सांकेतिक स्वरुप है, जहां से नव जीवन और चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होता है। नवरात्र में नौ दिनों तक शक्ति की ही आराधना की जाती है और इस आराधना के नौवें दिन प्रभु श्रीराम का जन्म होता है।

सनातन हिंदू नव वर्ष को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ही मनाया जाता है, क्योंकि, चैत्र मास से पहले फाल्गुन माह होता है, यह फागुन रस का महिना है जिसके देवता कामदेव होते हैं। कामदेव को मदन के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारण होली त्योहार को मदनोत्सव भी कहा जाता है। जब रस की उत्पत्ति होती है और कामदेव का उत्सव होता है तो आकर्षण का वेग प्रचंड होता है, जिसके बाद मदनोत्सव में मिलन होता है और युग्म बनता है। युग्म, अंड या बिंदु से स्वरुप में आता है और प्रकृति जिसमें स्वयं का संचार करती है। संचार के बाद जब बिंदु में विस्फोटन होता है तब प्रकृति खिलखिला उठती है, वातावरण में नये फूलों से, नई कोपलों से, नये जीवन से, प्रकृति नव वर्ष का स्वागत कर रही होती है। वह दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस है। यही आराधना की तपस्या का तंत्र कहलाता है।

सृष्टि नौ चरणों में है तभी नौ दिनों तक शक्ति के नौ रुपों की उपासना की जाती है। क्योंकि ब्रह्मांड का निर्माण शक्ति के संचार से हुआ, इसलिए शक्ति के इस ताप को आराधना एवं उपासना से मर्यादित करने के लिए नौ दिनों की उपासना की गई। जिससे शक्ति का प्रचंड वेग धीरे-धीरे समाप्त हो और फिर आराधना से शक्ति नौवें दिन सिद्धदात्री बनती है जिससे सारे संसार के लिए जीवन संभव हो जाता है। तद्पश्चात शक्ति सौम्य होती है और उससे फिर मर्यादा जन्म लेती है याने कि प्रकृति में प्रभु श्री राम का जन्म होता है, जो सृष्ठी को मर्यादीत कर देते हैं।

अब ब्रह्मांड में काम का वेग प्रचंड और जब काम की गति चरम पर तब प्रचंड वेग से बिंदु क्षरण फिर क्षरण से सृष्टि का उत्पन्न। इसलिए भी यह सृष्टि, शिव शक्ति की संतान कहलाती है। संतान के उत्पन्न होने से शक्ति का वेग नियंत्रण में आने से मर्यादा जन्म लेती है, और काम के प्रचंड वेग के कारण सृष्टि जो पागलों की तरह भाग रही होती है वह वेग समाप्त हो जाता है, और मर्यादा के जन्म से सृष्टि मर्यादित हो जाती है। मर्यादा अर्थात, श्रीराम जन्म लेते हैं तब सुर्य उच्च राशि में होता है और यहीं से ग्रीष्म की शुरुआत होती है।

ग्रीष्म ऋतु से तेज ताप बनता है, फिर ऋतुओं का वही क्रम चक्र चलता है इसे ही सृष्टि के आरंभ क्रम कहते हैं।

भारत में सदियों से विक्रम संवत पर आधारित चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा पर नव वर्ष मनाया जाता है। हिंदु नव वर्ष सभी समुदायों के लिए नवीनता का प्रतीक है, साथ ही नये वर्ष के शुभ अवसर पर नवरात्र के प्रारंभ में सभी नये संकल्प के साथ जीवन की नविन शुरुआत करते हैं। इसी प्रकार विक्रम संवत पुर्णतः वैज्ञानिक गणना पर आधारित है। इसके ऐतिहासिक कारण में बताया जाता है कि, भारत के महान सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित किया और चैत्र में राज्याभिषेक किया। इस शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष नववर्ष चैत्र में शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदु नव वर्ष और चैत्र नवरात्र हमारी सनातन संस्कृति में सभ्य समाज की सामर्थ्यता को समावित करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा और काल गणना की वैज्ञानिकता के प्रभाव और उसका जीवंत उदाहरण इस वर्ष आरंभ होने वाली प्रतिपदा या नववर्ष से देखा जा सकता है।

ऋतुओं के संधिकाल में आदिशक्ति की आराधना, उपासना, साधना और व्रत कर शक्ति संचयन का महापर्व वासंतिक नवरात्र आज 19 मार्च से आरंभ हो रहा है। विशेष यह है कि, उदया तिथि में अमावस्या होने से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय है। सुर्योदय के पश्चात प्रतिपदा प्रारंभ हुई, फिर भी भारतीय काल गणना के अनुसार पूरे दिन प्रतिपदा रहने पर तिथि अमावस्या मानी जाएगी और अमावस्या तिथि में उपस्थित प्रतिपदा में ही घर-घर कलश स्थापना कर नौ दिन व्रत, अनुष्ठान, पूजन, योग, सिद्धी आरंभ हो जाएंगे। भारतीय काल गणना की वैज्ञानिकता का स्वरुप यहां देखने को मिलता है कि, सनातन हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 पिछले संवत्सर की आज अमावस्या आरंभ हो गया।

रिंकेश बैरागी

इस वर्ष प्रतिपदा का क्षय होने पर भी नौ दिनों के नवरात्र है, 19 मार्च प्रातः 6 बजकर 41 मीनिट तक चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, और सुर्योदय के पश्चात प्रतिपदा आरंभ हो गई जो कि अगले दिन सुर्योदय के पूर्व 5.30 बजे तक रहेगी। उदयतिथि में अमावस्या रहते हुए थी प्रतिपदा का मान व्याप्त रहेगा। 26 मार्च को महाअष्टमी और 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी।

संपादकीय

खनन पर हो मनन

सत्ताधीशों की इच्छा शक्ति की कमी और प्रवर्तन एजेंसियों की लापरवाही से खनन माफिया के हौसल बुलंद हैं। कहीं न कहीं नागरिकों की उदासीनता भी इसके मूल में हैं। पंजाब के रोपड़ जिले की शिवालिक पहाड़ियों में हो रही तबाही उस भयावह स्थिति को दर्शाती है, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। वजह साफ है कि अंधाधुंध खनन से शिवालिक पहाड़ियों के पारिस्थितिकीय तंत्र को भारी क्षति पहुंच रही है। जो हमें यह भी बताता है कि नीति और प्रवर्तन के बीच खाई में पर्यावरणीय अपराध कैसे और किस तेजी से पनपते हैं। प्रशासन की नाक के नीचे खुदाई करने वाली भारी मशीनों का खुलेआम प्रयोग अवैध खनन हेतु किया जा रहा है। इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र की पूरी पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है। जो हमारे पर्यावरण के लिये एक गंभीर चुनौती है। यह क्षति शिवालिक पहाड़ियों के मूल पारिस्थितिक कार्यों मसलन भूजल पुनर्भरण, मृदा-स्थिरता और जैव-विविधता संरक्षण जैसे जीवन रक्षक लक्ष्यों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। दरअसल, यह शिवालिक पर्वतमाला भू-संरचना की दृष्टि से नयी बनी हुई है और स्वाभाविक रूप से अस्थिर है। निर्विवाद रूप से किसी भी स्थान पर होने वाली अनियंत्रित खुदाई से भूमि का कटाव बहुत तेजी से होता है। जिसके चलते वर्षा ऋतु और उसके बाद भूस्खलन की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती है। वहीं इन क्षेत्रों में गाद जमाव का संकट भी गहरा जाता है। कालांतर इसके चलते जल निकासी के पैटर्न में अप्रत्याशित बदलाव देखने में आता है। यह सर्वविदित है कि एक बार इन पहाड़ियों को अवैध रूप से काटकर समतल कर दिया जाता है तो उसके मूल स्वरूप को फिर प्राप्त कर पाना लगभग असंभव है। दूसरे शब्दों में कहें उस क्षेत्र विशेष का प्राकृतिक संरक्षण कवच हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ऐसे में प्राकृतिक सुरक्षा को नष्ट करने वाला विकास कालांतर आपदा का कारक बन सकता है।

दरअसल, यह ऐसा प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र होता है जो निचले मैदानी इलाकों को बाढ़ और जल संकट से बचाता है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि इस बाबत जवाबदेह अधिकारियों द्वारा दलील दी जाती रही है कि इस क्षेत्र में खनन की प्रक्रिया पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों के आधार पर की जाती रही है। साथ ही यह भी सफाई दी जाती है कि ऐसी स्वीकृतियों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन हकीकत तब उजागर हो जाती है जब स्थानीय लोग रात के समय होने वाले खनन कार्यों, निर्धारित सीमा से अधिक और बड़े पैमाने पर पहाड़ी इलाकों में कटाई होने के आरोप लगाते हैं। ऐसे में अधिकारियों की तमाम दलीलें खोखली ही साबित होती हैं। दरअसल,सवाल नियम-कानूनों की प्रभावकारिता का नहीं है बल्कि असली दिक्कत प्रवर्तन एजेंसियों की उदासीनता की है। जो वस्तु-स्थिति से अवगत होने के बावजूद इन आपराधिक कृत्यों के प्रति आंखें मूंदे रहती हैं। दरअसल, खनन कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को आपराधिक तत्वों व राजनेताओं का संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। इसमें दो राय नहीं है कि जब अवैध खनन के खिलाफ जमीनी स्तर पर निगरानी के बजाय महज कागजी कार्रवाई का सहारा लिया जाता है तो अवैध खनन को संबल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि यह अवैध खनन केवल पंजाब की शिवालिक पहाड़ियों के आसपास ही हो रहा है। पूरे भारत में, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तमाम क्षेत्रों में अवैध खनन लगातार पर्यावरण से जुड़े कानूनों की सीमाओं का उल्लंघन करता नजर आता है। अकसर खनन के लिये दिए गए परमिटों में अस्पष्टता और स्थानीय स्तर पर कमजोर निगरानी का फायदा उठाया जाता है। वह भी तब जब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के फैसलों में बार-बार इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि आर्थिक गतिविधियां पारिस्थितिकीय नुकसान की कीमत पर नहीं चलायी जा सकती। फिर भी, जमीनी स्तर पर, प्रवर्तन एजेंसियां या तो शक्तिहीन दिखाई देती हैं या निर्णायक कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति उनमें नजर नहीं आती। वास्तव में अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगाने के बजाय प्रतिबंधित क्षेत्रों का सख्त सीमांकन, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी तथा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है।

आसान नहीं भाजपा की पंजाब में वर्चस्व की राह

निर्मल संधू

गत चैदह मार्च को मोगा में अपनी बहुप्रचारित रैली की शुरुआत करते हुए अमित शाह को पगड़ी पहने और सिखों का लोकप्रिय जयघोष करते देखना एक दिलचस्प नज़ारा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर सिख सभाओं में पगड़ी पहनकर आते हैं। जो कोई भी भाजपा नेताओं को सिखों को लुभाने के वास्ते ऐसे हास्यास्पद सुझाव देता है, उसे पंजाब से जुड़े किसी भी राजनीतिक मामले पर सलाह देने से स्थाई तौर पर रोक देना चाहिए।

यह कोई राज़ नहीं है कि भाजपा में फ़ैसले शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं। यहां तक कि मीडिया को इंटरव्यू देने के लिए भी केंद्रीय नेतृत्व की मंज़ूरी ज़रूरी रहती है। जाहिर है, आने वाले विधानसभा चुनावों में चुनाव अकेले लड़ने के पार्टी के फ़ैसले का ऐलान करने से पहले अमित शाह ने सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे स्थानीय पार्टी नेताओं से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया था। जबकि कांग्रेस के ये दोनों पूर्व दिग्गज नेता सार्वजनिक तौर पर शिरोमणि अकाली दल के साथ चुनावी गठबंधन करने की वकालत कर रहे थे। यह रवनीत सिंह बिट्टू ही थे जिन्होंने ऐसे किसी भी गठबंधन का ज़ोरदार विरोध किया है; ऐसे में अगर कल को उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए, तो कोई हैरत नहीं।

स्थानीय लोगों के साथ सार्थक संवाद के अभाव में, गृह मंत्री ने अपने भाषण में पसंदीदा अलगाव के मुद्दों में से एक का सहारा लियाकृधर्मांतरण। भाजपा जिस 'बदलाव' का वादा कर रही है, यदि उसमें धर्मांतरण-विरोधी क़ानून भी शामिल है, तो चुनावी लिहाज़ से उसे कोई ख़ास सफलता नहीं मिलेगी। धर्मांतरण कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, जो आम पंजाबियों को परेशान कर रहा हो। मामूली आर्थिक फ़ायदों के लिए ईसाई धर्म अपनाने वाले ग़रीब लोगों से समाज या राज्य को कोई ख़तरा नहीं है। सबको अपने साथ लेकर चलने वाला पंजाब, धार्मिक आधार पर समाज में अलगाव से चुनाव जीतने के भाजपा के एजेंडे को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा।

आम तौर पर पंजाबी लोग अहंकारी नेताओं को सत्ता से बाहर करने के लिए वोट देते हैं। उनकी कोई पसंदीदा पार्टी शायद ही कभी रही है। पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिली ज़बरदस्त जीत का श्रेय 'आप' के नेतृत्व से किसी बड़ी उम्मीद के बजाय, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के कुशासन के लिए उन्हें दी गई सज़ा को ज़्यादा जाता है। हो सकता है कि अब वे 'आप' से भी मोहभंग महसूस कर रहे हों, लेकिन वे इतने नाराज़ भी नहीं हैं कि उसे सत्ता से ही बेदख़ल कर दें।

सिख राजनीतिक विचारक और लेखक, अजमेर सिंह के अनुसार 'भाजपा ने हरियाणा में जाटों को अलग-थलग करके और गैर-जाटों को एकजुट करके चुनाव जीता था। पंजाब में भी वह यही रणनीति अपना सकती हैकृसिख जाट वोटों को बांटना और हिंदू, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वोटों को एकजुट करना'। डेरा सचखंड बल्लां के प्रमुख को पद्मश्री से सम्मानित करना और उसके बाद दलित बहुल इलाके में गुरु रविदास को श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी का डेरा दौरा, ज़ाहिर तौर पर इसी रणनीति का हिस्सा हैं।

पंजाब के कुल वोटों में दलितों की हिस्सेदारी 32 प्रतिशत है और जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुरकृइन चार ज़िलों की 117 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों के नतीजों में वे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दलितों के बीच रविदासिया समुदाय एक बड़ा हिस्सा है। भाजपा इसी समुदाय पर दांव लगा रही है। भाजपा की इस चुनावी रणनीति को एक और चीज़ से भी मदद मिल रही हैकृदोषी डेरा प्रमुख राम रहीम की बार-बार पैरोल पर रिहाई। पंजाब के मालवा इलाके के कुछ हिस्सों में राम रहीम के बहुत सारे अनुयायी हैं और फिलहाल उसका पसंदीदा दल भाजपा है। ब्यास स्थित राधा स्वामी डेरा आमतौर पर राजनीतिक रूप से तटस्थ रहता है।

भाजपा की दलितों तक पहुंच बनाने की कोशिश भी शायद ही कामयाब हो जाए, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटर बंटे हुए हैं और अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन करते हैं। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी पंजाब में ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और इसीलिए भाजपा के लिए हरियाणा वाली सफलता को पंजाब में दोहराना मुश्किल होगा। यहां पर हालात पूरी तरह से उसके अनुकूल नहीं हैं। सिख आमतौर पर भाजपा से दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि भाजपा की राजनीति भड़काऊ होती है, एजेंडा सांप्रदायिक केंद्रित होता है, और वह डेरों को संरक्षण देती है। सिखों का मुख्य सिद्धांत है 'सरबत दा भला' (सबका कल्याण)। पंजाबी स्वभाव से ही धर्मनिरपेक्ष होते हैं। उग्रवाद के चरम पर होने के समय भी, गंभीर उकसावों के बावजूद, कोई बड़ा सांप्रदायिक विभाजन नहीं हुआ था।

सिखों को लुभाने के वास्ते, भाजपा ने पगड़ीधारी कई नेताओं को पार्टी में शामिल किया है। राजनीति को धर्म से जोड़ते हुए, वह अक्सर गुरु तेग बहादुर और साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करती है, और करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के बारे में दावे करती है; लेकिन इन सब बातों का कोई खास असर नहीं होता। इसके विपरीत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लगातार दोहराया जाने वाला यह नज़रिया कि सिख भी हिंदुओं का ही हिस्सा हैं, इस समुदाय को विशेष रूप से नाराज़ करता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंपस पर 'भगवा वर्चस्व' की कोशिशों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे।

भाजपा की सत्ता पाने की कोशिश का समर्थन किसानों और खेतिहर मज़दूरों द्वारा करने की संभावना कम ही है। पहले ही, तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के साल भर चले विरोध प्रदर्शनों ने भाजपा नेतृत्व को बैकफुट पर धकेल रखा है। तिस पर 'बीज विधेयक', 'बिजली विधेयक' और अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते ने उन्हें फिर से आंदोलन की राह पर ला खड़ा किया है। मोगा में अमित शाह किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बात कर सकते थे।

भाजपा की राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां भी पंजाब को रास नहीं आती। इन नीतियों से आज़ादी के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा आर्थिक असमानता देखने को मिली है, और मुट्ठी भर 'गोदी सेठों' के हाथों में अकूत संपत्ति जमा हो गई है। धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना, समाज में भय को हवा देना, और लोगों का ध्यान भटकाने वाली राजनीति करनाकृ ये सब भले ही व्यापक आर्थिक संकट को छिपा लें और चुनावी जीत दिला दें, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।

पंजाब के दौरों के दौरान, मोदी-शाह की जोड़ी ने न तो पंजाब के मूल मुद्दों को छुआ और न ही राज्य को मौजूदा मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई सोची-समझी योजना पेश की। क्या भाजपा के पास पंजाब को उस 'आर्थिक संकट' से बचाने का वह दृष्टिकोण है, जिसकी कमी के लिए अतीत की सत्ताधारी पार्टियां कुख्यात रही हैं? क्या यह राज्य के सिर चढ़े उस कर्ज़ का बोझ हल्का करने में मदद कर सकती है, जो पिछले कई सालों में बेतरह ज्यादा खर्च, सोचे-समझे बिना कर्ज़ लेने और 'रेवड़ी योजनाओं' में पैसे की बर्बादी की वजह से जमा हो गया है?

तथापि सूबे में अपने अब तक के निराशाजनक प्रदर्शन और सत्ता तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली ढेरों रुकावटों के बावजूद, इस बार भाजपा की पंजाब में पैठ बनाने की कोशिश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। भाजपा की 'वोट जीतने वाली मशीन' की ताकत और पहुंच को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसके संगठनात्मक कौशल, आर्थिक ताकत, आरएसएस का समर्थन और एक 'अनुकूल' चुनाव आयोग, ये ऐसे बेजोड़ फायदे हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। पार्टी नेतृत्व की राजनीतिक रणनीतियां और जातिगत समीकरण अक्सर मनचाहे नतीजे देते हैं।

संस्मरण की सशक्त आवाज़ को मिला सम्मान

डॉ. वेद मित्र शुक्ला

हिंदी साहित्य की बहुआयामी और सशक्त रचनाकार ममता कालिया को उनके चर्चित संस्मरण जीते जी इलाहाबाद (2021) के लिए वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाना हिंदी साहित्य जगत के लिए एक सुखद क्षण है।

2 नवम्बर, 1940 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में जन्मी ममता कालिया हिंदी साहित्य की उन रचनाकारों में हैं जिनकी रचनात्मकता किसी एक विधा तक सीमित नहीं रही। कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, निबंध, संस्मरण और पत्रकारिता के साथ लगभग हर विधा में उन्होंने अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कराई है। हिंदी कहानी के परिदृश्य पर उनका लेखन सातवें दशक से लगातार सक्रिय रहा है और लगभग आधी सदी के रचनात्मक काल में उन्होंने दो सौ से अधिक कहानियां लिखीं, जो समकालीन जीवन की विडंबनाओं, मध्यवर्गीय संघर्षों और स्त्री-अनुभवों की सजीव अभिव्यक्ति हैं। साहित्यिक संस्कार वाले उस परिवार में ममता जी जन्मी जहां, पिता विद्याभूषण अग्रवाल हिंदी और अंग्रेज़ी साहित्य के विद्वान तथा शिक्षक थे। शिक्षा और जीवन के विभिन्न चरणों में भारत के कई शहरों में रहना उनके व्यक्तित्व और लेखन को व्यापक सामाजिक अनुभवों से समृद्ध करता रहा। तभी उनकी रचनाओं में भारतीय शहरी जीवन का यथार्थ, बदलते पारिवारिक संबंध और स्त्री की आत्मसजगता गहरे रूप में दिखाई देती है।

कहानी के क्षेत्र में ममता कालिया की विशिष्ट पहचान है। उनकी संपूर्ण कहानियां अब तक ममता कालिया की कहानियां (2017) शीर्षक से दो खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके चर्चित कहानी संग्रहों में छुटकारा, एक अदद औरत, सीट नं. छह, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन, मुखौटा, निर्मोही, थिएटर रोड के कौए और पच्चीस साल की लड़की विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन कहानियों में समकालीन जीवन की विसंगतियां, मध्यवर्गीय परिवारों के अंतर्विरोध और स्त्री की आत्मसंघर्षशील चेतना सशक्त रूप में उभरती है।

उपन्यास विधा में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण है। बेघर (1971), नरक दर नरक (1975), प्रेम कहानी (1980), लड़कियां (1987), एक पत्नी के नोट्स (1997), दौड़ (2000), अंधेरे का ताला (2009), दुक्खम?दुसुक्खम? (2009), कल्चर वल्चर (2016) और सपनों की होम डिलीवरी (2017) जैसे उपन्यास हिंदी कथा साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। इनमें बदलते सामाजिक मूल्य, उपभोक्तावादी संस्कृति और स्त्री की बदलती भूमिकाएं अत्यंत संवेदनशील ढंग से चित्रित हुई हैं। कविता, नाटक और संस्मरण लेखन में भी ममता कालिया ने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कविता संग्रहों में खांटी घरेलू औरत और कितने प्रश्न करूं उल्लेखनीय हैं। नाटकों में यहां रहना मना है और आप न बदलेंगे चर्चित रहे हैं। संस्मरण विधा में उनकी पुस्तक कितने शहरों में कितनी बार (2010) और नवीनतम जीते जी इलाहाबाद पाठकों और आलोचकों दोनों के बीच विशेष रूप से सराही गई है।

सीधे-सीधे संस्मरण जीते जी इलाहाबाद की बात करें तो पाते हैं कि एक लेख से शुरू हुए इस पुस्तक के पूर्ण होने की यात्रा में एक शहर की स्मृतियों का आख्यान होने के साथ-साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक परिवेश की जीवंत झांकी भी है, जिसमें इलाहाबाद (अब प्रयागराज) की बौद्धिक परंपरा और रचनात्मक वातावरण को आत्मीयता से दर्ज किया गया है। यानी ममता कालिया ने संस्मरण विधा को निजी स्मृतियों के कथन से आगे ले जाकर उसे एक व्यापक सांस्कृतिक और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ा है। यह कृति किसी एक व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत न होकर उस साहित्यिक शहर की जीवित स्मृति है, जिसने आधुनिक हिंदी साहित्य को दिशा दी। ममता कालिया ने शहर के उस वातावरण को पुनर्सृजित किया है जहां साहित्य, संवाद और बौद्धिक बहसें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा थीं। वे बताती हैं कि यहां पैदल चलना किसी विवशता का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मीय सामाजिक जीवन का संकेत था। इस शहर की सांस्कृतिक संरचना में लेखकों, पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की सक्रिय उपस्थिति थी, जिसने उसे हिंदी साहित्य की उर्वर भूमि बना दिया।

संस्मरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका शब्द चित्रात्मक शिल्प है। इसमें उपेन्द्रनाथ अश्क, नरेश मेहता, अमरकांत, ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह और रवीन्द्र कालिया जैसे साहित्यकारों के जीवंत चित्र मिलते हैं, जो उस दौर की साहित्यिक संस्कृति को मूर्त रूप देते हैं। इन चित्रों में प्रशंसा के साथ मानवीय कमजोरियों का भी सहज उल्लेख है, जिससे संस्मरण की विश्वसनीयता और बढ़ जाती है। इस प्रकार जीते जी इलाहाबाद एक ऐसे साहित्यिक नगर का सांस्कृतिक दस्तावेज़ है जो रचनात्मकता, प्रतिरोध और आत्मीयता की परंपरा को जीवित रखता है।

वर्ष 2017 में ममता जी को उपन्यास दुक्खम?दुसुक्खम? के लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, सावित्री बाई फुले स्मृति सम्मान और लमही सम्मान जैसे अनेक अलंकरण उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। अब 2025 में जीते जी इलाहाबाद के लिए मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी साहित्यिक साधना की एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है।

टूट रहा दुबई में बसने का सुनहरा सपना

हेमंत पाल

बीते कुछ सालों में भारत के कई बड़े उद्योगपति, निवेशक और उच्च आय वर्ग के लोग तेजी से दुबई और खाड़ी देशों की ओर रुख करते दिखाई दिए। कम टैक्स, वैश्विक जीवनशैली और आसान बिजनेस माहौल ने उन्हें आकर्षित किया। लेकिन, हाल के भू-राजनीतिक तनावों और क्षेत्रीय अस्थिरता ने इस प्रवृत्ति पर नए सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में दुबई जैसे देशों में बसना उतना सुरक्षित और स्थायी विकल्प है जितना माना जाता है, या फिर यह केवल टैक्स बचाने और विलासितापूर्ण जीवन की चाह का परिणाम है! यह सवाल अब गंभीर बहस का विषय बन चुका है।

एक दशक में दुबई भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी ठिकानों में से एक बनकर उभरा है। खासकर अमीर भारतीयों और उद्योगपतियों के बीच वहां बसने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में भारतीय निवेशकों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ती गई और कई बड़े कारोबारी परिवारों ने वहां महंगी प्रॉपर्टी खरीदकर स्थायी निवास बना लिया।

इस आकर्षण के पीछे सबसे बड़ा कारण दुबई का टैक्स ढांचा है। दुबई में व्यक्तिगत आयकर नहीं है, जबकि भारत में उच्च आय वर्ग को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना पड़ता है। यही कारण है कि कई लोग अपनी आय और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए खाड़ी देशों में बसने का फैसला करते हैं। इसके अलावा दुबई का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र के रूप में पहचान और अपेक्षाकृत आसान कारोबारी नियम भी लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। हालांकि, दुबई जाने का कारण केवल टैक्स बचाना ही नहीं है। कई उद्योगपति और कारोबारी दुबई को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार मानते हैं। मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका के बीच स्थित होने के कारण दुबई व्यापार और लॉजिस्टिक्स के लिए एक रणनीतिक केंद्र बन चुका है। इसके अलावा दुबई में लग्जरी जीवनशैली, आधुनिक शहर, बेहतर परिवहन व्यवस्था और अपेक्षाकृत तेज प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी आकर्षण का कारण हैं। कई भारतीय पेशेवर और उद्यमी मानते हैं कि दुबई में कारोबार शुरू करना और विस्तार करना भारत की तुलना में आसान और तेज है। लेकिन, हाल के समय में पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों ने इस आकर्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

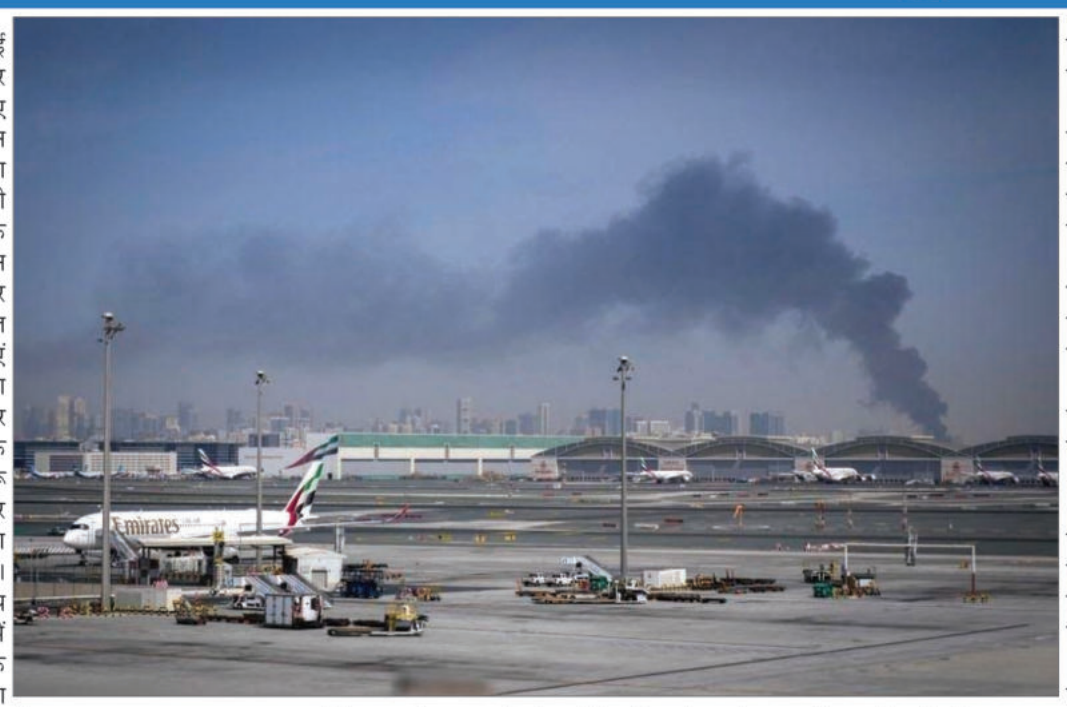

क्षेत्रीय संघर्षों और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने यह याद दिलाया है कि खाड़ी क्षेत्र पूरी तरह स्थिर नहीं है। जब भी पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ता है, तो वहां रहने वाले विदेशी नागरिकों की सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता बढ़ जाती है। ऐसे समय में कई लोग यह महसूस करने लगते हैं कि आर्थिक लाभ के बावजूद किसी दूसरे देश में स्थायी रूप से बसना हमेशा सुरक्षित विकल्प नहीं होता। इसके विपरीत भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक और अपेक्षाकृत स्थिर देश है। यहां मजबूत संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो नागरिकों को दीर्घकालिक सुरक्षा और अधिकार प्रदान करती है। भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ रही है और निवेश तथा उद्यमिता के नए अवसर लगातार सामने आ रहे हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम, डिजिटल अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ने देश को वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक बना दिया है। ऐसे में कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए विदेश बसना हमेशा दीर्घकालिक रूप से सही फैसला नहीं होता।

एक और महत्वपूर्ण पहलू सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव का है। भारत छोड़कर विदेश में बसने वाले कई लोगों को समय के साथ यह महसूस होता है कि अपने समाज, संस्कृति और परिवार से दूर रहना आसान नहीं होता। दुबई जैसे देशों में भले ही भारतीय समुदाय बड़ा हो, लेकिन वहां की नागरिकता व्यवस्था और सामाजिक ढांचा अलग है। अधिकांश विदेशी नागरिकों को वहां स्थायी नागरिकता नहीं मिलती, जिससे उनका भविष्य हमेशा अनिश्चित बना रहता है। हाल के वर्षों में यह भी देखने को मिला है कि कुछ लोग विदेश में रहने के बाद वापस भारत लौटने का निर्णय ले रहे हैं। भारत की बढ़ती आर्थिक संभावनाएं, तकनीकी विकास और बेहतर जीवन के अवसर इस बदलाव के पीछे प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए कई आर्थिक सुधारों और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशों ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है।

दरअसल, विदेश में बसना या निवेश करना कोई गलत निर्णय नहीं है। लेकिन केवल टैक्स बचाने या अल्पकालिक लाभ के लिए स्थायी रूप से देश छोड़ देना एक बड़ा फैसला होता है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। जरूरी यह है कि लोग आर्थिक लाभ के साथ-साथ सुरक्षा, स्थिरता, सामाजिक जुड़ाव और भविष्य की संभावनाओं जैसे पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार करें।

दुबई और खाड़ी देशों का आकर्षण अपनी जगह है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने यह सवाल जरूर खड़ा किया है कि क्या केवल आर्थिक कारणों से विदेश बसना सही फैसला है। भारत आज तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और यहां अवसरों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में शायद यह समय है जब लोग केवल टैक्स के नजरिए से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने फैसलों पर पुनर्विचार करें।

418 करोड़ से आधुनिक बनेगा प्रदेश का 65 वर्ष पुराना डैम

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में चंबल नदी पर स्थित गांधीसागर डैम में जलविद्युत गृह 418 करोड़ में आधुनिक रूप में तैयार होगा। इसमें क्षमता वृद्धि के साथ इसका नवीनीकरण भी होगा। इससे बिजली उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होगी। गांधीसागर जल विद्युत गृह की इकाइयों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता वृद्धि का काम सरकार कृषि वर्ष के अंतर्गत कर रही है। गांधीसागर जल विद्युत गृह की 5-23 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से चल रही है।

वर्तमान तकनीकी मानकों के अनुरूप विद्युत उत्पादन प्रणाली को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इन इकाइयों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। परियोजना के अंतर्गत सभी जनरेटिंग इकाइयों में आधुनिक टरबाइन एवं जनरेटर का किया जाएगा। साथ ही उन्नत सुरक्षा, निगरानी एवं पर्यवेक्षण नियंत्रण प्रणाली के साथ आधुनिक कंट्रोल पैनलों की स्थापना की जाएगी।

संचालन होगा बेहतर

बेहतर संचालन नियंत्रण एवं दूरस्थ निगरानी के लिए आधुनिक ऑटोमेशन सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। इसके साथ ही परिचालन सुरक्षा तथा प्रभावी जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आइसोलेशन गेट्स का उन्नयन किया जाएगा। बाढ़ से सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए उच्च क्षमता के डी वॉटरिंग पंपों की स्थापना की जाएगी। लंबे समय तक चलने के उद्देश्य से परियोजना में समस्त पाइपलाइन, पावर एवं कंट्रोल केबल, सिग्नल वायरिंग तथा अन्य सहायक प्रणालियों का प्रतिस्थापन भी किया जाएगा।

कार्यक्षमता में सुधार

परियोजना चरणबद्ध तरीके से गांधीसागर पर पूरी की जाएगी। इसमे 2,2,1 इकाइयों को अलग-अलग चरणों में लिया जाएगा। प्रत्येक चरण में चयनित इकाइयों पर कार्य किया जाएगा जबकि शेष इकाइयां वर्तमान व्यवस्था के माध्यम से विद्युत उत्पादन जारी रखेंगी। विद्युत गृह की कार्य क्षमता, सुरक्षा में वृद्धि होगी।

इनका कहना..

गांधीसागर जल विद्युत गृह की 5-23 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयां पिछले 65 वर्षों से अधिक समय से चल रही है। वर्तमान तकनीकी मानकों के अनुरूप विद्युत उत्पादन प्रणाली को अधिक सक्षम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से इन इकाइयों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा। इससे क्षमता में वृद्धि के साथ आधुनिक रूप से निगरानी से लेकर पूरा काम होगा।- अरुण यादव, इंजीनियर, गांधीसागर पावर जनरेशन

10 मिनट की मुलाकात के लिए शहर बंधक...!

माही की गूंज, रतलाम।

मंगलवार को एक आंदोलन ने पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। 10 मिनट की मुलाकात के लिए शुरू हुए इस विवाद ने ऐसा रूप ले लिया कि आम जनता को 40 डिग्री की तपती धूप में करीब 4 घंटे तक सड़कों पर जाम में फंसे रहना पड़ा।

खनिज विभाग की कार्रवाई के विरोध में जीवनसिंह शेरपुर ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट घेराव का ऐलान किया था। हालांकि रतलाम पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने उन्हें सेजावता और धोसीगांव के पास रोक दिया, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर मिशा सिंह को मौके पर बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी की। उनका आरोप था कि प्रशासन जनता की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आम लोग भीषण गर्मी में परेशान हो रहे हैं। शहर के एंट्री पॉइंट और महू-नीमच फोरलेन पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग के कारण कई मार्ग बंद रहे, जिससे लोगों को अपने घर पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि यह विवाद 7 दिन पहले जावरा क्षेत्र में डंपर जब्ती की कार्रवाई से शुरू हुआ था। खनिज विभाग द्वारा दो डंपरों को अवैध परिवहन के आरोप में जब्त किए जाने के बाद शेरपुर ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जो अब बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है।

प्रदर्शन के दौरान अवैध उत्खनन पर कार्रवाई रोकने, किसानों की समस्याओं के समाधान, गेहूं खरीदी, कर्ज अदायगी और अन्य जनहित के मुद्दों को लेकर 11 प्रमुख मांगें प्रशासन के सामने रखी गई हैं। फिलहाल प्रशासन स्थिति को संभालने में जुटा है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक आंदोलन के चलते आम जनता को इतनी बड़ी परेशानी क्यों झेलनी पड़ी।

कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, टंकी की निकाली अर्थी

माही की गूंज, राजगढ़ (ब्यावरा)।

घरेलू गैस की किल्लत और लगातार बढ़ती कीमतों के विरोध में ब्लाक और शहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा नगर में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीपल चैराहा से शहर के प्रमुख मार्गों में रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए गैस टंकी की अर्थी निकाली साथ ही सुभाष चैक पर नाली में पाइप डालकर चूल्हा जलाने का प्रतीकात्मक प्रयास किया, जिससे गैस संकट की गंभीरता को दर्शाया जा सके। धरना-रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अन्य लोग शामिल हुए।

इस दौरान कांग्रेसजनों ने कहा कि लगातार बढ़ती गैस कीमतों ने आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों का जीवन कठिन बना दिया है। वहीं गैस की किल्लत के कारण लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी नीतियों के कारण पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं,जिससे महंगाई चरम पर पहुंच गई है। उन्होंने मांग की है कि गैस सिलेंडर के दामों में तुरंत कमी की जाए और आम जनता को राहत दी जाए। कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने और जनहित में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

इस दौरान पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. भरत वर्मा, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव, ब्लाक अध्यक्ष राहुल दांगी, शहर अध्यक्ष कपिल शिवहरे, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमन अरोरा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष रचना भार्गव, पार्षद ज्ञानू विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

इन्हे लगेगा नि:शुल्क एचपीवी वैक्सीन

माही की गूंज, रतलाम।

सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है, इसे रोकने के लिए जिले में निःशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन 28 फरवरी से शुरू किया गया जो 90 दिन तक किया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए ऐसी सभी बालिका जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया है एवं 15 जन्मदिन नहीं मनाया है, वे निःशुल्क वैक्सीनेशन करवा सकती है।

वैक्सीनेशन कराने के लिए यू विन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराया जा सकता है या सीधे केंद्र पर आकर भी वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन के लिए आयु संबंधी कोई भी प्रमाण पत्र अथवा स्वयं के घोषणा पत्र के आधार पर भी सहजता से वैक्सीनेशन कराया जा सकता है। 90 दिन में 18917 बच्चों को वैक्सीनेशन किया जाना हैं। अब तक 18 दिन में कुल 971 बालिकाओं ने वैक्सीन लगाया जा चुका हैं।

जिले में अब तक 971 को लगे वैक्सीन

प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एपी सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 971 बालिकाओं का वैक्सीनेशन किया है। सिविल अस्पताल आलोट में 134, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ताल में 129, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजना में 77, सिविल अस्पताल जावरा में 228, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपलोदा में 185, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नामली में 50, बाल चिकित्सालय रतलाम में 82, मेडिकल कॉलेज रतलाम में 10, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैलाना में 76 बालिकाओं का वैक्सीनेशन किया है।

सीएमएचओ ने कहा वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित

सीएमएचओ ने शंका समाधान करते हुए स्पष्ट किया कि एचपीवी वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। यदि किसी के घर में कैंसर संबंधी कोई मरीज नहीं है, तब भी एचपीवी का वैक्सीनेशन कराया जाना आवश्यक है, ताकि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो सके। एचपीवी का टीका प्रजनन क्षमता को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है, एचपीवी का टीका मासिक धर्म पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि मासिक धर्म होने के दौरान भी एचपीवी का टीका लगवाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी का गार्डशील का एक बार वैक्सीनेशन करना पर्याप्त है। एचपीवी का टीका सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने में 93 से 100 प्रतिशत तक प्रभावशीलता प्रदान करता है। सीएमएचओ सभी अभिभावकों से अपनी 14 वर्षीय बालिका का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर निशुल्क एचपीवी वैक्सीनेशन करने का आग्रह किया है।

एक साथ जली 8 चिताएं...

इंदौर।

जिले में माहौल उस समय बेहद गमगीन हो गया जब एक साथ 8 लोगों की अर्थियां उठी। अग्निकांड में जिंदा जले आठ लोगों का तिलक नगर मुक्तिधाम में एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी के चेहरों पर एक दर्द साफ नजर आ रहा था। बता दें ग्रेटर ब्रजेश्वरी कॉलोनी में देर रात कार चार्जिंग के दौरान हुई आगजनी की घटना में पुगलिया परिवार के 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल है।

कैसे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, इंदौर के बंगाली चैराहे के पास स्थित ब्रजेश्वरी कॉलोनी में देर रात में भीषण हादसा हो गया। यहां पुगलिया परिवार के घर में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में पुगलिया परिवार की गर्भवती बहू समेत आठ लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।

बताया जा रहा है कि पुगलिया परिवार के घर के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुबह करीब 4 बजे चार्जिंग पॉइंट में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कार में आग लग गई। आग तेजी से फैलते हुए घर तक पहुंच गई और अंदर रखे गैस सिलिंडरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद घर में रखे सिलेंडरों में धमाके शुरू हो गए। लोगों की मानें तो एक के बाद एक चार सिलेंडर फटे, जिससे मकान का एक हिस्सा ढह गया। तीन मंजिला मकान में पुगलिया परिवार के सदस्य ऊपरी मंजिल में सो रहे थे जबकि इनके यहां बिहार से मनोज सेठिया का परिवार आया हुआ था जो ग्राउंड फ्लोर में सो रहा था। इसी सेठिया परिवार के छह लोगों की मौत हादसे में हुई है जबकि दो लोग पुगलिया परिवार के हैं। वहीं घटना में तीन लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।

हादसे का दर्दनाक पहलू

जांच में पाया गया कि लोगों की जान बच सकती थी लेकिन घर में इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे हुए थे। आग के दौरान बिजली सप्लाई बंद हो जाने से ये लॉक नहीं खुल सके, जिससे अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हुई। दरवाजे तोड़कर रेस्क्यू करना पड़ा। वहीं घर में रखे गैस सिलेंडरों में विस्फोट होने की वजह से हादसे ने और भी भीषण रूप धारण कर लिया।

खसरे से मासूम की मौत, एएनएम निलंबित

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में आदिवासी गांव की 7 वर्ष की मासूम मोनिका की खसरे से मौत हो गई। जिला अस्पताल के प्रभारी सीएमएचओ डॉ एपी सिंह के अनुसार मासूम को उपचार के लिए निजी अस्पताल में 12 मार्च को भर्ती परिजन ने किया। इलाज के दौरान ही मासूम की मौत हो गई। मामले में एक एएनएम को निलंबित किया गया है।

जिले के आदिवासी क्षेत्र बाजना विकासखंड के रावटी के करीब भैतला गांव की निवासी थी। बाजना सेक्टर के इस गांव की निवासी मासूम को खसरे की बीमारी की सूचना निजी अस्पताल से मिलने के बाद मेडिकल विभाग का दल पहुंचा। मामले में एक एएनएम को निलंबित किया है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ वर्षा कुरील को जांच के लिए सोमवार को गांव में भेजा गया वे अपनी रिपोर्ट मंगलवार को देंगी। इन सब के बीच मासूम की मौत की सूचना मिलने के बीच सीएमएएचओ डॉ संध्या बेलसरे अवकाश पर चली गई।

19 दिन पहले भी हो चुकी मौत

19 दिन पूर्व जिले में एक आंगनबाड़ी केंद्र पर टीकाकरण के बाद दो बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। टीका लगने के करीब एक घंटे बाद दोनों बच्चों को उल्टी-दस्त की शिकायत का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान 10 माह के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि डेढ़ साल का दूसरा बच्चा अस्पताल में उपचार करा रहा था। बिलपांक थाना क्षेत्र के नयाखेड़ा गांव की आंगनबाड़ी केंद्र में 19 दिन पूर्व दोपहर बच्चों को टीके लगाए गए थे। गांव के धर्मेंद्र मालवीय के 10 माह के बेटे पियांशु और देवीलाल मालवीय के डेढ़ साल के बेटे नित्यांशु सहित कुल चार बच्चों को टीकाकरण किया गया था। रात में 10 माह के बच्चे की मौत हो गई थी। धर्मेंद्र मालवीय के 10 माह के बेटे को कुल तीन टीके लगाए गए थे। इनमें से दो टीके हाथ पर और एक टीका जांघ पर लगाया गया था। टीकाकरण दोपहर 12:30 से 1 बजे के बीच किया गया था।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम मिली चिट्ठी

माही की गूंज, राजगढ़ (ब्यावरा)।

जिले के ब्यावरा शहर में उस समय सनसनी फैल गई, जब अहिंसा द्वार के समीप कन्हैयालाल बीड़ी कंपनी के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से लिखी एक संदिग्ध चिट्ठी मिली। चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, कलेक्टर, एसपी,डीएसपी,लाडली बहना सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं।

जानकारी के अनुसार बीड़ी कारखाना नंबर-2 के मैनेजर हेमराज मेहर ने दरवाजा खोला तो गेट के पास तीन कागज फोल्ड हालत में रखे मिले। कागज खोलकर पढ़ने पर वे सन्न रह गए। तीनों पर्चियों में अलग-अलग नामों के साथ धमकी भरा कंटेंट लिखा था। एक पर्ची में बीड़ी कारखाना और पास ही दुकान संचालित करने वाले बंटी पालीवाल का नाम दर्ज था। सूचना मिलते ही सिटी थाना प्रभारी वीरेंद्र धाकड़ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

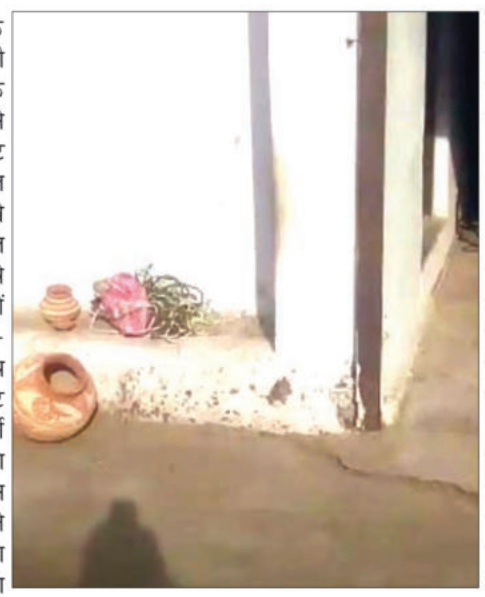

पुलिस ने आसपास के क्षेत्र का मुआयना कर ओल्ड एबी. रोड़ और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। जिस स्थान पर चिट्ठी मिली,वहां सीसीटीव्ही. कैमरा नही लगा है। नगरपालिका कार्यालय से अहिंसा द्वार के बीच जो कैमरे लगे है,उनमें संदिग्ध दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में चिट्ठी रखने वाले की पहचान करना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है।

चिट्ठी में नाम आने से किराना व्यापारी बंटी पालीवाल भी सहम गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी उनका नाम इस तरह की चिट्ठी में आना चिंताजनक है। चिट्ठी के पहले कागज में प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी लाड़ली बहना, जुआ-सट्टा,लारेंस विश्नोई। वहीं दूसरे कागज में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, सी डा.मोहन यादव, लाडली बहना, जुआ-सट्टा, लारेंस विश्नोई गेंग और तीसरे कागज में लाड़ली बहना, प्रधानमंत्री मोदी,सीएम मोहन,बीड़ी नं. 2 तेरी कारखाना,बंटी पालीवाल,एसपी,डीएसपी, पुलिस,कलेक्टर के बारे में अपशब्द लिखे। उसके बाद नीचे लारेंस विश्नोई गेंग लिखा हुआ है।

शहर ब्यावरा थानाबप्रभारी वीरेन्द्र धाकड़ का कहना है कि, अहिंसा द्वार के समीप बीड़ी कारखाने के दरवाजे के पास तीन फोल्ड कागज मिले है,उसमें लारेंस विश्नोई गैंग के नाम से अपशब्द लिखे गए है।मामले में तकनीकी जांच की जा रही है साथ ही आसपास के सीसीटीव्ही. कैमरों की जांच कर लोगों से पूछताछ की जा रही है।

मूल्यांकन समिति की बैठक हुई आयोजित

माही की गूंज, मंदसौर।

जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कलेक्टर अदिती गर्ग की अध्यक्षता में हुई। जिला पंजीयक प्रशांत पाराशर ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि वर्ष 2026-27 हेतु जिले की गाईड-लाईन (अचल सम्पत्ति) के अनन्तिम दर निर्धारित किये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई, सर्वसम्मति से उप-जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तावित दरों को अनुमादित किया गया है। प्रस्तावित अनंतिम दरें जिला पंजीयक कार्यालय मंदसौर एवं सभी उप पंजीयक कार्यालयों में जनता के सुझाव हेतु प्रदर्शित की गयी है। दरों के संबंध में यदि कोई सुझाव पस्तुत करना चाहता है तो मय दस्तावेजी साक्ष्य के दिनांक 20 मार्च शाम 5:00 बजे तक जिला पंजीयक कार्यालय / उप-पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

अर्धनारी बनकर खेत में गड़ा सोना बताकर लाखों की ठगी

माही की गूंज, खरगोन।

जिले के मंडलेश्वर थाना क्षेत्र के सूल्याखेड़ी गांव में एक महिला के साथ लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने महिला को खेत में गड़ा सोना होने का झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए आभूषण और नगदी सहित कुल 9.95 लाख रुपये का सामान बरामद किया है।

ठगी की शुरुआत तब हुई जब आरोपी राहुल नाथ ने महिला का भेष धारण कर खुद को काजल दीदी बताया। उसने महिला को विश्वास दिलाया कि वह अर्धनारी है और उसके भाग्य में अपार धन लिखा है। आरोपियों ने महिला को बताया कि उसके खेत में 11 क्विंटल सोना दबा हुआ है, जिसे निकालने के लिए 5 तोला सोना देकर विशेष पूजा करनी होगी।

10 मार्च को खेत में पूजा के दौरान आरोपियों ने एक मटकी में महिला के सोने के गहने जैसे चूड़ियां, पेंडेंट, चेन, अंगूठी और 51 हजार रुपये नकद रखवा लिए। पूजा के बीच में ही काजल दीदी ने महिला को फूल बहाने के लिए पास की नहर पर भेज दिया। जब महिला वापस लौटी, तब तक आरोपी गहनों से भरी मटकी लेकर फरार हो चुके थे।

पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा के निर्देशन में टीम ने निगरानी कैमरों की रिकॉर्डिंग और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर धार जिले के सादलपुर में दबिश दी। पुलिस ने घेराबंदी कर राहुल (25) और विक्की (19) को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उनके पास से 9.04 लाख रुपये के आभूषण, 21 हजार रुपये नकद और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है।

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे अंधविश्वास में न फंसें और जमीन में गड़ा धन निकालने का दावा करने वाले लोगों से सतर्क रहें।

पिता बोले-नाबालिग बेटी को छल-कपट से फंसाया

माही की गूंज, महेश्वर।

अभिनेत्री मोनालिसा के लापता होने का मामला सामने आया है। उनके पिता जय सिंह भोसले ने फरमान खान और उसके परिवार पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस अनुविभागीय अधिकारी स्वेता शुक्ला को लिखित शिकायत सौंपकर बेटी को प्रेम जाल में फंसाने का संदेह जताया है।

ढापला मार्ग, महेश्वर निवासी जय सिंह भोसले के अनुसार उनकी बेटी मोनालिसा को 11 मार्च को अगवा किया गया था। घटना के कुछ समय बाद संदेश प्रेषण माध्यम और सामाजिक माध्यमों पर उनकी बेटी के निकाह की तस्वीरें सामने आईं, जिससे परिवार गहरे सदमे में है।

पिता का दावा है कि उनकी बेटी नाबालिग है और उसे छल-कपट तथा साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि मोनालिसा को एक संगठित समूह द्वारा प्रेम जाल में फंसाया गया है। जय सिंह भोसले का कहना है कि उनकी बेटी हमेशा आज्ञाकारी रही है और वह माता-पिता की जानकारी के बिना ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती।

शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी आशंका जताई है कि मोनालिसा का भविष्य, सम्मान और जीवन गंभीर खतरे में है। उनका कहना है कि उसे डरा-धमकाकर या बहला-फुसलाकर इस स्थिति में लाया गया है। जय सिंह ने पुलिस प्रशासन से तत्काल और निष्पक्ष जांच कर बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी स्वेता शुक्ला ने बताया कि मोनालिसा के माता-पिता का आवेदन प्राप्त हुआ है। उनके साथ मोनालिसा की फिल्म के निर्देशक सरोज मिश्रा भी उपस्थित थे। आवेदन में अपहरण सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनकी विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच प्रारंभ कर दी है।

25 दिन से बंद रास्ते ने रोका व्यापार, सड़क तैयार फिर भी आवागमन ठप

माही की गूंज, बड़वानी।

शहर में पुराने कलेक्ट्रेट से पीएम कक्ष तक की सड़क खुदाई के कारण रास्ता बंद होने से क्षेत्र के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 80 से 100 दुकानों का व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है और व्यापारियों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।

व्यापारी महेश यादव का कहना है कि रास्ता बंद होने के कारण ग्राहक दुकानों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। दुकानदारों ने अपने स्तर पर वैकल्पिक रास्ता बनाने की कोशिश भी की, लेकिन स्थान कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। अब व्यापारियों की मांग है कि प्रशासन कम से कम दोपहिया वाहनों के लिए रास्ता खोल दे, ताकि उनका काम फिर से शुरू हो सके।

दुकानदारों को आगामी गणगौर पर्व की भी चिंता है। उनका कहना है कि पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से माता की सवारी इसी मार्ग से निकलती आ रही है। यदि सड़क नहीं खोली गई, तो यह परंपरा प्रभावित हो सकती है। व्यापारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण हुए 25 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद इसे अनावश्यक रूप से बंद रखा गया है।

इस संबंध में नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि यह सड़क विशेष योजना के अंतर्गत बनाई जा रही है। उनके अनुसार सड़क निर्माण को अभी लगभग 14-15 दिन ही हुए हैं और नियम के अनुसार नई सड़क को मजबूत होने के लिए कुछ समय तक बंद रखना आवश्यक होता है, अन्यथा वह शीघ्र क्षतिग्रस्त हो सकती है।

उन्होंने कहा कि वे स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगी और व्यापारियों के साथ चर्चा कर कोई उपयुक्त समाधान निकालने का प्रयास करेंगी, जिससे पर्व के दौरान लोगों को परेशानी न हो और व्यापार भी प्रभावित न हो।

महाराष्ट्र ले जाई जा रही भैंसें पकड़ी गईं, दो आरोपी गिरफ्तार

माही की गूंज, खंडवा।

जिले में अवैध पशु परिवहन के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। पंधाना थाना पुलिस ने मंगलवार को सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक मालवाहक वाहन से 14 भैंसों को मुक्त कराया। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन भी जब्त किया है।

पंधाना थाना प्रभारी दिलीप देवड़ा के अनुसार मंगलवार शाम सूचना मिली थी कि एक आयशर मालवाहक वाहन क्रमांक एमपी 12 जेडएफ 9855 में भैंसों को क्रूरता से भरकर महाराष्ट्र की ओर ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस दल ने पंधाना-रुस्तमपुर मार्ग पर घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया।

जांच के दौरान वाहन में 14 भैंसें ठूंस-ठूंसकर भरी हुई पाई गईं। पुलिस ने तुरंत पशुओं को मुक्त कर वाहन जब्त कर लिया। बरामद भैंसों की कीमत लगभग 60 हजार रुपये बताई गई है।

मौके से पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें जाहिद (32) निवासी खानशाहवली और सद्दाम (30) निवासी इमलीपुरा शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध पंधाना पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध पशु परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

तीन साल से अंधेरे में जी रही लकवाग्रस्त महिला, बिजली कनेक्शन कटा

माही की गूंज, बड़वानी।

बड़वानी में एक लकवाग्रस्त महिला पिछले तीन वर्षों से बिना बिजली के अंधेरे में जीवन यापन कर रही है। महिला के दोनों पैर काम नहीं करते, जिसके कारण वह बिस्तर से उठने में असमर्थ है और पूरी तरह दूसरों पर निर्भर है।

जानकारी के अनुसार महिला के घर की बिजली लगभग तीन वर्ष पहले बिल जमा न होने के कारण काट दी गई थी। तब से वह बिना रोशनी और पंखे के रह रही है। बीमारी के चलते वह चलने-फिरने में असमर्थ है और लकवे से पीड़ित बताई जा रही है।

समाजसेवी अजित जैन को स्थानीय लोगों के माध्यम से महिला की स्थिति की जानकारी मिली। रात में जब वे उससे मिलने पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि महिला भीषण गर्मी और मच्छरों से परेशान थी।

अजित जैन ने महिला के लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था शुरू करवाई है। उन्होंने प्रशासन से महिला का उचित उपचार कराने और बिजली कनेक्शन जल्द बहाल करने की मांग की है।

पड़ोसियों के अनुसार महिला के परिजन कभी-कभार उसकी देखभाल के लिए आते हैं, लेकिन नियमित देखरेख नहीं हो पाती। इस स्थिति में प्रशासन और समाज से महिला की सहायता के लिए आगे आने की अपील की गई है।

निवाली में बीआरसी 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

माही की गूंज, बड़वानी।

इंदौर लोकायुक्त की टीम ने बुधवार सुबह बड़वानी जिले के निवाली में कार्रवाई करते हुए ब्लॉक संसाधन समन्वयक महेंद्र सिंह राठौर को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक संबंधित उप अभियंता को भी आरोपी बनाया गया है।

लोकायुक्त उप पुलिस अधीक्षक सुनील तमांग के अनुसार शिक्षक जितेंद्र सोनी ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके विद्यालय में बालिका शौचालय निर्माण के लिए 20 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी।

शिक्षक का आरोप है कि ब्लॉक संसाधन समन्वयक और उप अभियंता ने उनसे कहा कि वे 15 हजार रुपये में कार्य पूरा कर लें और शेष 5 हजार रुपये में से 2-2 हजार रुपये उन्हें देने होंगे तथा 1 हजार रुपये बड़वानी में देने की मांग की गई थी।

शिकायत की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त टीम ने योजना बनाकर शिक्षक को बुधवार को राजपुर स्थित ब्लॉक संसाधन समन्वयक के घर के पास एक स्वचालित नकद निकासी यंत्र पर 5 हजार रुपये देने भेजा। जैसे ही महेंद्र सिंह राठौर ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया।

लोकायुक्त द्वारा इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

मस्तिष्क की सेहत पर मंडराता प्लास्टिक कणों का खतरा

प्लास्टिक के सूक्ष्म कण पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कण अथवा प्लास्टिक के छोटे-छोटे टुकड़े हवा से लेकर पानी और खाने तक हर चीज में पाए गए हैं। अब डोनेट किए गए 52 मानव मस्तिष्कों पर हुए एक अध्ययन से इस बात की पुष्टि हुई है कि ये माइक्रोप्लास्टिक कण मस्तिष्क के अंदरूनी हिस्सों में जमा हो सकते हैं। शोधकर्ताओं को मस्तिष्क के हर सैंपल में पॉलीइथाइलीन और दूसरे पॉलिमर के निशान मिले और उन्होंने देखा कि हाल के सैंपल में पुराने सैंपल के मुकाबले इनकी मात्रा ज्यादा थी।

वैज्ञानिकों ने पाया कि 2024 में लिए गए सैंपल में प्लास्टिक की मात्रा 2016 में देखी गई मात्रा से अधिक थी,जिससे पता चलता है कि मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर लगातार बढ़ रहा है। नई रिसर्च का नेतृत्व अमेरिका की न्यू मेक्सिको यूनिवर्सिटी में टॉक्सिकोलॉजी के प्रोफेसर मैथ्यू कैम्पेन ने किया है। उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक के उपयोग में सावधानी बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा दुनियाभर में बढ़ता प्लास्टिक उत्पादन प्रदूषण की एक मुख्य वजह है।

विशेषज्ञों ने यह भी जांच की कि क्या कुछ खास परिस्थितियां इन वस्तुओं के जमाव को और बढ़ा देती हैं। उन्होंने डिमेंशिया के मरीज़ों के एक ग्रुप को देखा जिनके मस्तिष्क में दूसरे सैंपल के मुकाबले तीन से पांच गुना ज्यादा प्लास्टिक के कण थे। वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे गए टुकड़ों के आकार देखकर हैरान गए। इन टुकड़ों में साफ-सुथरे गोलों के बजाय,कई दांतेदार, परत जैसी संरचनाएं थी। ऐसे ऊबड़-खाबड़ आकार वाले माइक्रोप्लास्टिक चिकने, गोल आकार वाले माइक्रोप्लास्टिक की तुलना में कोशिकाओं के साथ अलग तरीके से क्रिया कर सकते हैं। पहले किए गए अनेक अध्ययनों में विभिन्न मानव अंगों,जैसे रक्त धमनियों, किडनी और प्लेसेंटा में प्लास्टिक के अपशिष्ट पाए गए हैं। प्रयोगशाला में चूहों के मॉडल पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि थोड़े समय के लिए सिंथेटिक पार्टिकल के संपर्क में आने से भी कई अंगों में सूजन हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इन पार्टिकल की वजह से खास बीमारियों का पता लगाना मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्लास्टिक का संपर्क लगभग हर जगह होता है।

एक अन्य रिसर्च टीम ने देखा कि मस्तिष्क के ऑलफैक्ट्री बल्ब में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद थे, जिससे पता चलता है कि इन टुकड़ों के नर्वस टिशू में घुसने के कई रास्ते हैं। ध्यान रहे कि ऑलफैक्ट्री बल्ब मस्तिष्क का वह हिस्सा है जहां गंध की प्रोसेसिंग होती है। नई रिसर्च इस बात के प्रमाण देती है कि माइक्रोप्लास्टिक कण मस्तिष्क के फ्रंटल कॉर्टेक्स में और भी गहराई तक जा सकते हैं। ये कण मस्तिष्क की कुशाग्रता या दूसरे कार्यों पर कैसे असर डाल सकते हैं, इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि डिमेंशिया वाले लोगों के दिमाग में अक्सर फिल्टरिंग सिस्टम कमजोर हो जाते हैं, जिससे यह साफ नहीं होता कि प्लास्टिक की ज्यादा मात्रा ऐसी स्थितियों में योगदान करती है या यह मात्रा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि दिमाग उन्हें ठीक से साफ नहीं कर पाता।

जानवरों पर किए गए एक अध्ययन में माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क को याददाश्त में मामूली बदलाव और मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में शुरुआती सेलुलर स्ट्रेस (कोशिकीय तनाव) के संकेतों से जोड़ा गया है। पर्यवेक्षकों का मानना ??है कि इंसानों पर हुए अध्ययन में यह साफ होने में सालों लग सकते हैं कि क्या माइक्रोप्लास्टिक कण सीधे स्नायु संबंधी दिक्कतें लाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी जिस तरह प्लास्टिक का व्यापक इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह सूक्ष्म प्लास्टिक हवा, खाने और पानी के जरिए हर जगह फैल रहा है, उसे देखते हुए इस समस्या का कोई जल्दी समाधान नहीं निकल सकता।

कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जब माइक्रोप्लास्टिक को दिमाग और दूसरे जरूरी अंगों में जाने से रोकने के लिए औद्योगिक अपशिष्ट के निपटान के बारे में कड़े नियम बनाना बहुत जरूरी है। कुछ अन्य विशेषज्ञों ने कहा कि किस प्लास्टिक की छोटे-छोटे टुकड़ों में विखंडित होने की सबसे ज्यादा संभावना है,इस पर हमें और डेटा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक कणों के आकार और रासायनिक बनावट में अंतर मायने रखता है।

समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने बताया है कि समुद्रों में प्लास्टिक के कचरे के बारे में शुरुआती चेतावनियों को ज्यादातर नज़रअंदाज़ किया गया था, इसलिए इंसानी सेहत के लिए जरूरी उपायों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ प्लायमाउथ के प्रोफेसर रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा है कि इन प्लास्टिक कणों को सेहत के नतीजों से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। थॉम्पसन ने ही सबसे पहले 'माइक्रोप्लास्टिक' शब्द का इस्तेमाल किया था। प्लास्टिक कणों का पता लगाने के नए तरीके वैज्ञानिकों को वह देखने में मदद कर रहे हैं जो कभी दिखाई नहीं देता था।

पिछले दस सालों में एडवांस्ड इमेजिंग टूल्स और रासायनिक विश्लेषण ज्यादा सटीक हो गए हैं, जिससे नतीजों पर भरोसा बढ़ता है। फिर भी, कई लोगों को चिंता है कि समस्या मौजूदा टेस्टों से ज्यादा बड़ी हो सकती है। अध्ययनों में उम्र,स्वास्थ्य की स्थिति और लाइफस्टाइल के फैक्टर्स का मुद्दा भी उठाया गया है, जो एक व्यक्ति के शरीर में दूसरे की तुलना में माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा पर असर डाल सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक की इतनी विविधता होने से इसके हानिकारक प्रभाव का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

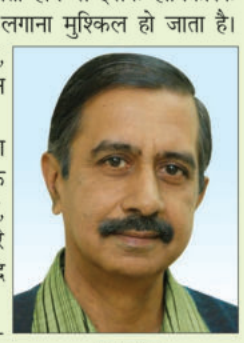

मुकुल व्यास

पॉलीस्टाइनिन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीइथाइलीन का आमतौर पर जिक्र किया जाता है, लेकिन दूसरे पॉलीमर भी मौजूद रहते हैं।

कुछ छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं,जबकि दूसरे रेशों में बदल जाते हैं जो टिशू में उलझ सकते हैं। विशेषज्ञों ने जोर देकर कहा कि माइक्रोप्लास्टिक से घबराने की कोई बात नहीं है लेकिन इसके बारे में जागरूकता रहनी चाहिए। ज्यादा जागरूकता से मैन्युफैक्चरिंग के तरीकों, उपभोक्ता की पसंद और अवशिष्ट प्रबंधन में बदलाव आ सकते हैं। जैसे-जैसे ग्लोबल प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ेगा, भविष्य में इन प्लास्टिक कणों के अधिक स्तर को रोकने के लिए और कदम उठाने होंगे। माइक्रोप्लास्टिक के बारे में भले ही कुछ सवाल बने रहें, वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों,जानवरों और प्रयोगशाला में लगातार मिले नतीजे सावधानी बरतने की जरूरत की ओर इशारा करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक दिमाग की कोशिकाओं या रक्त धमनियों को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है,इसकी गहरी समझ से बचाव के रास्ते खुल सकते हैं।

16 निर्माण कार्यों के साथ गीता भवन का भूमि पूजन

माही की गूंज, उज्जैन।

सिंहस्थ की दृष्टि से उज्जैन को 664 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन को बदनावर से 8 लेन सुपर एक्सप्रेस हाईवे की सौगात दी है। दिल्ली जाने के लिए देवास-इंदौर के पास से सीधे गरोठ हाईवे भी मिला है।

इसके अलावा 3839 करोड़ लागत का नेशनल हाईवे गुजरात के द्वारका से असम में चीन सीमा तक बनेगा। यह एनएच गुजरात के सोमनाथ और उज्जैन के महाकाल को सीधे जोड़ेगा। केंद्रीय केबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देते हुए कहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश चहुंओर प्रगति कर रहा है और मध्यप्रदेश इस विकास यात्रा में हर कदम पर भारत सरकार के साथ है।

सिंहस्थ विकास कार्यों के लिए 3600 करोड़ के प्रावधान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों के मद्देनजर 13.50 करोड़ से अधिक के विकास कार्य जारी हैं। इसके साथ ही वर्ष 2026-27 में 3600 करोड़ के कार्यों के लिए नए प्रावधान किए हैं।

उन्होंने कहा कि भगवान मंगलनाथ की कृपा से मंगल बेला में लगभग 664 करोड़ के अलग-अलग कार्यों में नए मार्ग, विक्रम आरओबी, सड़क चैड़ीकरण, नए सीसी रोड भी शामिल हैं। उज्जैन में 77 करोड़ से अधिक लागत के गीता भवन निर्माण के लिए भी भूमि-पूजन किया गया है। प्रदेश में विकास का क्रम जारी है।प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भगवन, गांवों में आदर्श ग्राम, वृंदावन ग्राम बनाए जा रहे हैं।

किसान कल्याण वर्ष में उल्लेखनीय कार्य

मोहन यादव ने कहा कि, किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। पशुपालन विभाग ने सवा साल में 25 प्रशितक दूध उत्पादन बढ़ाया है। किसानों को 5 से 8 रुपये लीटर अधिक मूल्य का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जरूरी बदलाव किए गए हैं। स्कूली बच्चों को साइकिलें, ड्रेस, किताबें निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। टॉपर बच्चों को स्कूटी, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप की सौगात मिल रही है। अब प्रदेश के बच्चों को स्कूलों में निःशुल्क दूध के पैकेट मिलेंगे। इसके लिए माता यशोदा के नाम से नई योजना की शुरुआत की गई है।

सांस्कृतिक अभ्युदय का शंखनाद- राज्यपाल

इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि उज्जैन में भव्य गीता भवन सहित करोड़ों की लागत के विकास कार्यों का भूमि-पूजन भविष्य के सांस्कृतिक अभ्युदय का शंखनाद है। इंदौर और जबलपुर के बाद आज उज्जैन में भव्य गीता भवन तैयार करने के लिए भूमि-पूजन हुआ है। यह गीता भवन प्रदेशवासियों में सुसंस्कारों का बीजारोपण और सनातन ज्ञान को आगे बढ़ाने वाला दूरदर्शी कदम है। उन्होंने आगे कहा कि यहां युवाओं, शोधार्थियों और नागरिकों को भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन और संस्कृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगी। जो समाज में भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान और मूल्यों की परंपरा के विस्तार में सहायक सिद्ध होगा। यह विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और संकल्प से सिद्धि का प्रतीक है। इन नगरीय विकास योजनाओं से निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

कलेक्टर ने मूल्यांकन केन्द्र का किया निरीक्षण

माही की गूंज, आलीराजपुर।

सर प्रताप उत्कृष्ट विद्यालय आलीराजपुर में हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर ने मूल्यांकन केन्द्र का औचक निरीक्षण करते हुए मूल्यांकन कार्य का जायजा लिया। उन्होंने केन्द्र में मूल्यांकन कार्य करने वाले शिक्षकों की ड्यूटी, बैठक व्यवस्था, मॉडल आन्सर शीट, सुरक्षा व्यवस्था, मूल्यांकनकर्ताओं के आने के समय आदि की व्यवस्था के विषय में जानकारी ली।

इस दौरान प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी एवं एसडीएम सुश्री निधि मिश्रा ने बताया कि इस मूल्यांकन केन्द्र में दसवीं तथा बारहवीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य किया जा रहा है। मूल्यांकनकर्ता शिक्षक सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक मूल्यांकन करते है। एक दिन में एक शिक्षक औसतन 40-45 पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते है। कलेक्टर श्रीमती माथुर द्वारा विषयवार पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कक्षों का निरीक्षण किया गया एवं शिक्षकों से मूल्यांकन,मॉडल उत्तर पुस्तिका के बारे में जानकारी ली। अभी तक कक्षा बारहवीं की लगभग 17100 और कक्षा दसवीं की 14895 उत्तर पुस्तिकाएं का मूल्यांकन किया जा चुका है शेष उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने कहा कि मूल्यांकन कार्य में आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी लगाएं, जिससे समयावधि में मूल्यांकन कार्य सम्पादित कराया जा सके। उन्होंने शिक्षकों से भी अपील की कि वे मूल्यांकन कार्य में पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करें। इस दौरान सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं मूल्यांकन अधिकारी श्री संजय परवाल एवं संबंधित शिक्षक मौजूद रहे।

लकड़ी परिवहन पर बड़ी कार्यवाही

माही की गूंज, धार।

वन मण्डल धार द्वारा लगातार सख्त कार्यवाही करते हुए लकड़ी तस्करों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर 16 मार्च 2026 की रात्रि में वन मण्डल अधिकारी धार विजयानंथम टी.आर. के मार्गदर्शन में एक और बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वन परिक्षेत्र अधिकारी धार श्री सचिन सयदे ने बताया कि सूचना प्राप्त होने पर गश्ती एवं चेकिंग दल का गठन कर मौके पर भेजा गया। ग्राम धोलाहनुमान में पंचायत के सामने मार्ग पर जा रहे एक पिकअप वाहन को टीम द्वारा घेराबंदी कर रोका गया। वाहन क्रमांक एमपी 13 जे 1118 की तलाशी लेने पर उसमें जामुन की अवैध लकड़ी भरी पाई गई। वाहन चालक ने अपना नाम पवन पिता धीरज निवासी ग्राम मोहनपुरा तथा वाहन मालिक का नाम असलम खान पिता बशीर खान निवासी गुलमोहर कॉलोनी, धार बताया। चालक से लकड़ी कटाई एवं परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं पाया गया। तत्काल टीम द्वारा मौके पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए वाहन को जब्त कर वन परिक्षेत्र कार्यालय धार लाया गया। मामले में आगे की जांच कार्यवाही प्रचलित है। वाहन में लगभग 30 से 40 क्विंटल लकड़ी पाई गई, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 25,000 रुपये तथा वाहन का अनुमानित मूल्य लगभग 5,00,000 रुपये है। इस कार्यवाही में वन स्टाफ रामसिंह कनेल, गौरव तिवारी एवं कमल रावत (वन रक्षक, परिक्षेत्र धार) का योगदान रहा।

एनओसी नहीं दी तो किसान ने बैंक में बजाया ढोल

माही की गूंज, धार।

जिला मुख्यालय धार में संचालित एक निजी बैंक में एनओसी नहीं मिलने से परेशान किसान ने नए अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बैंक खुलने के बाद ग्राम चंदावड़ निवासी किसान विजय पाटीदार ढोल और दोस्तों को लेकर बैंक में पहुंच गए। यहां पर काफी देर तक ढोल बजवाकर बैंक के अंदर डांस किया।

अचानक इस तरह की स्थिति को देखकर अधिकारी-कर्मचारी और ग्राहक हैरान हो गए। कुछ देर बाद बैंक के मैनेजर मौके पर पहुंचे और किसान को समझाइश दी गई। उन्हें शाम तक एनओसी देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ढोल लेकर किसान बैंक से बाहर हुआ। हालांकि छोल बजने के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया कि अचानक हुआ क्या है।

किसान परिवार ने जताई नाराजगी

प्रदर्शन को रोकने के लिए पहुंचे मैनेजर से किसान परिवार के सदस्यों की काफी बहस हुई। परिवार के सदस्यों का कहना था कि किसान कई मोर्चों पर परेशान चल रहे हैं। आर्थिक दिक्कतें चल रही है। इसके बावजूद समय पर ऋण चुकाया गया है, लेकिन एनओसी नहीं दी जा रही है। काम छोड़कर एनओसी मांगने के लिए आना पड़ता है।

बैंक मैनेजर द्वारा बताया गया कि केसीसी ऋण देने का विभाग और एनओसी जारी करने का विभाग अलग है, इसलिए देर लगी है। शाम तक दे दी जाएगी। किसान विजय पाटीदार का कहना है कि ÷अगर शाम तक उन्हें एनओसी नहीं दी गई, तो वह बैंक के बाहर धरने पर बैठकर आंदोलन करेंगे.÷ किसान का यह अनोखा विरोध अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानें क्या है पूरा मामला

किसान विजय पाटीदार ने बताया कि उनके द्वारा बैंक से 13 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिया गया था। डेढ़ माह पूर्व उनके द्वारा पूरा ऋण चुका दिया गया है। बैंक से ऋण पूर्ण चुकता का लेटर मांगा गया था, लेकिन डेढ़ माह से चक्कर लगवाए जा रहे हैं। इसके कारण उन्हें मजबूरी में इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। उन्होंने बैंक के किसानों के प्रति लापरवाह रवैये को लेकर भी दुख जताया है। पाटीदार ने कहा कि 24 घंटे में उन्हें एनओसी नहीं मिली तो वह बैंक के सामने धरना देंगे।

ई-विकास प्रणाली पर एक दिवसीय प्रशिक्षण

माही की गूंज, आलीराजपुर।

किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत आलीराजपुर के विकासखंड कट्ठीवाड़ा की जनपद पंचायत के सभा कक्ष में ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत ई-टोकन के माध्यम से उर्वरक वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में पटवारी, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक, कृषि विस्तार अधिकारी तथा समिति प्रबंधकों को जिले के मास्टर ट्रेनर्स द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान ई-विकास प्रणाली के अंतर्गत आधार नंबर के माध्यम से किसानों के ई-टोकन जनरेशन,फार्मर रजिस्ट्री में खसरा जोड़ने की प्रक्रिया तथा किसानों को सरल और पारदर्शी तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराने के उपायों की जानकारी दी गई।

उप संचालक कृषि चैहान ने बताया कि, इस प्रणाली के लागू होने से उर्वरक वितरण में लगने वाली लंबी कतारों, कालाबाजारी,अनियमित वितरण एवं बिचैलियों की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा, जिससे किसानों को समय पर और सहज रूप से लाभ मिल सकेगा।

इस दौरान उप संचालक कृषि एस. एस. चैहान, तहसीलदार सुनील डावर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जी. एस. प्रजापति, सहायक संचालक कृषि रंजीत डावर एवं राजू सोलंकी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महिला को लिफ्ट देकर की मारपीट

माही की गूंज, धार।

जिले के धामनोद क्षेत्र में खलघाट से धरमपुरी जा रही 26 वर्षीय महिला के साथ लूटपाट और मारपीट का मामला सामने आया है। एक अज्ञात बाइक सवार ने मदद के बहाने महिला को लिफ्ट दी और सुनसान रास्ते पर ले जाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी ने महिला का मोबाइल और पर्स लूट लिया और विरोध करने पर पत्थर से सिर फोड़ दिया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए महिला को धामनोद से धार जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है।

कपड़े खरीदने निकली थी पीड़िता

खरगोन जिले के झिरनिया (अंबादोचड़) निवासी तैय्यबा मंगलवार को कपड़े खरीदने खलघाट आई थी। महिला यहां खलघाट से धरमपुरी जाने के लिए खड़ी थी। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धरमपुरी छोडने की बात करते हुए लिफ्ट दी। वहीं थोड़ी दूर जाने पर सुनसान रास्ते पर आरोपी बाइक सवार ने गाड़ी रोककर महिला के साथ मारपीट की। मोबाइल और पर्स में रखे करीब दो हजार रुपए छीन लिए। जब महिला ने विरोध किया, तो हमलावर ने दुपट्टे से उसका गला दबाया और सिर पर भारी पत्थर से वार कर दिया। लहुलुहान हालत में महिला वहीं पड़ी रही। जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया।

धार अस्पताल में उपचार

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बामनपुरी से घायल महिला को 108 एंबुलेंस की मदद से धामनोद अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद महिला को धार रेफर किया, जहां जिला अस्पताल में उसका उपचार किया जा रहा है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले के साथ ही आरोपी की तलाश में जुट गई है।

इंदौर-उज्जैन सिक्सलेन रोड में प्लास्टिक सरिए का हो रहा इस्तेमाल?

माही की गूंज, उज्जैन।

इंदौर और उज्जैन के बीच बन रही छह लेन की सड़क की गुणवत्ता को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया था कि यह सड़क प्लास्टिक के सरिए से बन रही है। इसके बाद ही 6 लेन की यह रोड विवादों में आ गई। लेकिन अब मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की तरफ से इस पर सफाई सामने आई है और उनकी तरफ से इस तरह के दावों को गलत बताया गया है।

जीएफआरपी नाम की सामग्री से बनाई जा रही सड़क

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर चल रही रील में किए गए दावों को भ्रामक बताया और कहा कि यह सड़क प्लास्टिक के सरिए से नहीं, बल्कि 'ग्लास फाइबर रीइन्फोर्स्ड पॉलीमर (जीएफआरपी)' नाम की सामग्री से बनाई जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि आमतौर पर 'फाइबर ग्लास' कहे जाने वाले जीएफआरपी में कांच के महीन रेशे और पॉलीमर रेजिन होते हैं, जो हल्का, मजबूत होता है और यह टिकाऊ भी होता है।

रील में बताए दावों को बताया गया गलत

मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंधक गणेश भाभर ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के बीच सड़क बनाने में स्टील के सरिए की जगह जीएफआरपी का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिन से सोशल मीडिया पर इस सड़क में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। रील में दावा किया गया कि सड़क में प्लास्टिक के सरिए का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यह सही नहीं है।

जीएफआरपी में कभी नहीं लगता है जंग

गणेश भाभर ने बताया कि स्टील के सरिए में जल्दी जंग लग सकता है, जबकि जीएफआरपी में कभी जंग नहीं लगता। उन्होंने कहा कि स्टील का सरिया भारी होता है, लेकिन जीएफआरपी बहुत हल्का है। भले ही इसका वजन कम है, लेकिन इसमें खिंचाव सहने की ताकत स्टील से ज्यादा है।

टीईटी के भूत से आखिर क्यों भयभीत है शिक्षक वर्ग

अगर नही हुए पास तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति, विरोध प्रदर्शन की तैयारी

माही की गूंज, पेटलावद।<
राकेश गेहलोत

आजकल शिक्षक संप्रदाय में एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चिंता बनी हुई है। जिसमें वर्षों से सेवा देने वाले शिक्षकों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए शासन द्वारा आयोजित पात्रता रूपी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जो असफल होंगे उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्ति के चाबुक का भय सता रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य हो गया है। इस निर्णय के बाद शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर राहत की मांग कर रहा है। लेकिन कई शिक्षक अब मान चुके हैं कि, केवल विरोध से कुछ नहीं होगा। इसलिए उन्होंने टीईटी की तैयारी शुरू भी कर दी है। कई शिक्षक तो स्कूलों में भी पढ़ाई करते दिख रहे हैं और कई शिक्षक बदनामी के डर से अपने-अपने घर में कई-कई घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट्सअप ग्रुपों पर इस समय शिक्षक, टीईटी सिलेबस के आधार पर सामान्य ज्ञान और अन्य विषयों से संबंधित सामग्री भी एक दूसरे को साझा कर रहे हैं।

जिनके 5 वर्ष बाकी उनको नहीं देनी होगी परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से अधिक है उन्हें हर हाल में टीईटी देना ही है। जिनका नौकरी का समय 5 वर्षो से कम बचा है उनके लिए परीक्षा अनिवार्य नहीं रहेगी। परीक्षा के लिए पात्र शिक्षकों के अनुत्तरित होने की स्थिति में नौकरी समाप्त हो सकती है। वहीं पदोन्नति चाहने वाले शिक्षकों के लिए भी टीईटी पास करना जरूरी कर दिया गया है। बहुत से शिक्षक अब यह मान कर चल रहे हैं कि, टीईटी से राहत नहीं मिलने वाली है। शासन ने 29 और 30 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा की तिथियां प्रस्तावित की थी, परंतु अब अगस्त माह में होना प्रस्तावित है। आवेदन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने वाली है। ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षक पढ़ाई में जुट गए हैं। उनका मानना है कि, समय रहते तैयारी करना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शासन-प्रशासन पर दबाव बनवाकर ज्ञापन और आंदोलन की रूपरेखा बना चुके हैं। पात्रता परीक्षा के मामले में शिक्षकों के एक समूह ने तो शिक्षकों से अपील की है कि, वे समय बर्बाद किए बिना, सिलेबस के अनुसार पढ़ाई शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि, अगर शिक्षक गंभीरता से तैयारी करें तो टीईटी पास करना कठिन नहीं है। टीईटी में केवल क्वालीफाई करना ही शिक्षकों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त होगा। गौरतलब है कि, फैल होने वाले शिक्षकों पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति की तलवार लटकी हुई है। यही वजह है कुछ शिक्षक तो किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते और पूरी तैयारी में जुट गए हैं। और शिक्षकों का दूसरा समुह है जो अग्नि परीक्षा से गुजरना नहीं चाहते हैं या उन्हें खुद की काबिलियत में संदेह है।

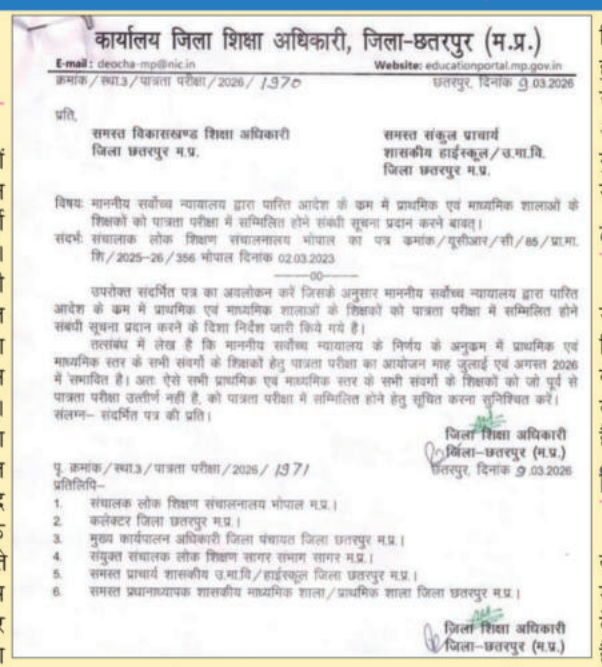

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-छतरपुर (म.प्र.)

E-mail: deocha-mp@nic.in Website: educationportal.mp.gov.in

क्रमांक/स्था.3/पात्रता परीक्षा/2026/1370 छतरपुर, दिनांक 9.03.2026

प्रति,

समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला छतरपुर म.प्र.

समस्त संकुल प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/उ.मा.वि. जिला छतरपुर म.प्र.

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने बावत्।

संदर्भ: संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल का पत्र क्रमांक/यूसीआर/सी/86/प्रा.मा.शि/2025-26/356 भोपाल दिनांक 02.03.2023

---00---

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी सूचना प्रदान करने के दिशा निर्देश जारी किये गये है।

तत्संबंध में लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुक्रम में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गो के शिक्षकों हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन माह जुलाई एवं अगस्त 2026 में संभावित है। अतः ऐसे सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के सभी संवर्गो के शिक्षकों को जो पूर्व से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नही है, को पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न- संदर्भित पत्र की प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/स्था.3/पात्रता परीक्षा/2026/1371 छतरपुर, दिनांक 9.03.2026

प्रतिलिपि-

1. संचालक लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल म.प्र.।
2. कलेक्टर जिला छतरपुर म.प्र.।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला छतरपुर म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सागर संभाग सागर म.प्र.।
5. समस्त प्राचार्य शासकीय उ.मा.वि/हाईस्कूल जिला छतरपुर म.प्र.।
6. समस्त प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला/प्राथमिक शाला जिला छतरपुर म.प्र.।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला-छतरपुर (म.प्र.)

दो वर्ष में मिलेगें तीन-चार मौके

जो शिक्षक इस परीक्षा के लिए पात्र हैं उनको एक दो नहीं बल्कि तीन से चार मौके 2 वर्षों में मिलेगें जिसमें शिक्षकों को परीक्षा पास करनी होगी। वर्ष 2010 के बाद के भर्ती हुए शिक्षकों को पात्रता परीक्षा नहीं देना है। क्योंकि वो पूर्व से इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर चयनित हुए है।

विरोध की तैयारी में शिक्षक

शिक्षकों ने अपने साथ हो रही ना इंसाफी पर खुल कर भड़ास निकाली। इस समय हर जगह शिक्षक इसी मुद्दे पर बहस करते दिख रहे हैं। पात्रता परीक्षा को लेकर देश, प्रदेश सहित झाबुआ जिले में भी बिगुल बज चुका है और आगामी आंदोलन को लेकर प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षा एवं उससे संबंधित संभावित आदेशों के कारण शिक्षक समाज में व्यापक चिंता एवं असंतोष की स्थिति निर्मित हुई है। शिक्षक हितों की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा ÷टेट संघर्ष समिति÷ का गठन किया गया।

इस संबंध में विभिन्न शिक्षक संघ शिक्षक के हितों के इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन के साथ एकजुट हो गए हैं। संघ के सभी जिला, ब्लॉक एवं संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आव्हान किया है जिसमें संघर्ष समिति द्वारा 20 मार्च 2026 को ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन एवं ज्ञापन और 24 मार्च 2026 जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने का आव्हान किया है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के सम्बन्ध में मुख्य बिंदु

1. ऐसे सभी शिक्षक जो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए है और जिनकी सैवानिवृ?ती में 5 वर्ष से अधिक समय शेष है, उनहें 2 वर्ष के अंदर टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते है, तो उन्हें सेवा से पृथक या अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जा सकता है।

3. ऐसे शिक्षकों को सेवा समाप्ति पर नियम अनुसार दैय अंतिम लाभ (टर्मिनल बेनीफिट्स) प्रदान किए जाएगा।

04 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन 4 अगस्त 2026 तक संभावित है।

आखिर क्यों टीआई दोलसिंग डोडियार सस्पेंड...?

माही की गूंज, झाबुआ।

जिले में अपराधियों, शराब माफियाओं का बोलबाला तो है ही पर इससे भी अधिक अब जिले में पुलिस की अपनी रंगधारी भी किसी से कम नहीं है। जिले की पुलिस जिले में किसी भी अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब तो है ही लेकिन अब जिले की पुलिस तो खुद अपनी मनमानी कार्रवाई के साथ कानून के कटघरे में खड़ी है और गुंडा प्रवृति की तरह अपने आप को प्रचलित कर पुलिस द्वारा हर मामले में रिश्वत लेना तो आम हो गया है।

जिले के प्रत्येक थाने-चैकी की पुलिस शराब माफिया एवं अन्य नशीले पदार्थ बेचने वालों से स्थाई मासिक बंदी के रूप में रिश्वत लेती ही है। उक्त रिश्वत पुलिस को मिलने वाली सरकारी वेतन की तरह नियमित होती है। वहीं थाने, चैकी पर कोई भी मामले आए जिसमें अपराध दर्ज हुए मामले में भी अपराधी व फरियादी दोनों पक्षों से कार्रवाई करने एवं चालान पेश होने तक रिश्वत ले लेती है। तो कई मामले दर्ज होना चाहिए ऐसे मामले होते हैं लेकिन पुलिस रिश्वत लेने के चलते मामले दर्ज नहीं करती। तो कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें पुलिस, फर्जी मामला दर्ज कर मोटी रकम वसूलती है। तो वही जिले की पुलिस की कारस्तानिया ऐसी कई सामने आई है जिसमें असल अपराधी को फरियादी बना देती है और जो किसी भी मामले में अपराधी नहीं होता है उसे अपराधी बना देती है। इन्ही पुलिस की कारस्तानियों में अपराध दर्ज होने के बाद ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें अपराध में संबंधित सामान्य धाराएं होती है लेकिन रिश्वत के साथ उसे बड़ा मामला पुलिस बना देती है और कई ऐसे बड़े मामले होते हैं उन मामलों को पुलिस सामान्य व छोटा मामला बताकर मामला दर्ज करती है।

ऐसे में जिले की पुलिस की भूमिका किसी अपराधी या गुंडा प्रवृत्ति से कम नहीं है इसी कड़ी में बुधवार को जैसे ही समाचारो के माध्यम से सामने आया कि, करीब 2 महीने पहले ही कल्याणपुरा थाने पर पदस्थ हुए टीआई दोलसिंह डोडियार को सस्पेंड कर दिया गया। उक्त जानकारी के बाद टीआई दोलसिंह डोडियार के सस्पेंड होने पर कई भिन्न तरीके की चर्चाएं चली और सवाल एक ही की आखिर कल्याणपुरा टीआई डोडियार साहब ने आखिर कौन सी कारस्तानी नई कर दी जिसके बाद साहब को सस्पेंड होना पड़ा।

इन्हीं चर्चाओं में सामने आया कि, टीआई डोडियार कहने को भले ही दो माह के करीब कल्याणपुरा थाने पर पदस्थ थे लेकिन कल्याणपुरा का कोई व्यक्ति नाम से तो ठीक शक्ल से भी नहीं पहचानते। जिसका कारण यह कि, डोडियार साहब ने स्थानीय लोगों से सीधा कोई संवाद नहीं किया न हीं बाजार में कभी निकले।

इसी बीच चर्चा में सस्पेंड होने का कारण सामने यह आ रहा है कि, कोई बड़ा अपराध किसी भी थाने चैकी में दर्ज होता है तो जिला पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाकर अनुमति लेना होती है। मामले में सामने आ रहा है कि, कल्याणपुरा थाना अंतर्गत किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था एवं जिसका मामला थाने में दर्ज हुआ। टीआई साहब ने उक्त मामले को बड़ा बताकर गैंगरेप का मामला धाराएं बढाकर दर्ज कर दिया। जबकि पुलिसिया सूत्र अनुसार ही उक्त मामला गैंगरेप का नहीं था। वहीं उक्त मामले में जब गैंगरेप के रूप में एफआईआर में दर्शाया गया उसके पूर्व जिला अधीक्षक से कोई अनुमति भी नहीं ली और न ही टीआई द्वारा अवगत करवाया गया।

टीआई की उक्त कारस्तानी की ठोस शिकायत होने के बाद एसपी को टीआई दोलसिंह डोडियार को सस्पेंड करना पड़ा। पर सवाल यह कि, अगर टीआई साहब ने किसी बेगुनाह को अपराधी बनाकर गैंगरेप का रूप देकर मामला दर्ज कर लिया है...? तो क्या साहब को सस्पेंड करने के साथ कार्य की इतिश्री हो गई...?

जिसमें लोगों का कहना है कि, अगर पुलिस ने इस तरह का अपराध किया है तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होना चाहिए न कि सस्पेंड कर कार्य की इतिश्री होना चाहिए।

दोलसिंग डोड़ियार सस्पेंड टीआई

गैस की किल्लत नहीं, विपक्ष बना रहा है माहौल

युद्ध की स्थिति में जरूरी चीजों के खर्च पर सबक लेने की आवश्यकता - श्री राठौर

माही की गूंज, रायपुरिया/पेटलावद।

देश भर में गैस की किल्लत की खबरों के बीच झकनावदा से भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर ने क्षेत्र में किसी प्रकार की गैस की किल्लत नहीं होने की बात कही है। उन्हाने कहा, किसी भी गंभीर परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं के उपयोग के लिए सबक लेने की आवश्यकता है।

माही की गूंज से हुई बातचीत में झकनावदा क्षेत्र के भाजपा मंडल अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की किसी भी विकट परिस्थिति में तैयार है और विपक्ष जबरन के आरोप ओर प्रत्यारोप लगा कर घटिया राजनीति कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने की बात कही। वर्तमान में गैस सिलेंडर की कमी को लेकर देश भर के अलग-अलग हिस्सों से गैस सिलेंडरो की कमी की खबरे आ रही है और विपक्ष भी इस मुद्दे पर लगातार सरकार की घेरा बंदी करने में लगा है। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर गैस की किल्लत को लेकर मिंस बनाकर मजाक उड़ाया जा रहा है। जिले की कलेक्टर नेहा मीना पहले ही जिले में किसी प्रकार से गैस की कमी नहीं होने की बात कह चुकी है। ऐसे में भाजपा नेताओं द्वारा भी लगातार गैस सिलेंडर किल्लत को लेकर अपनी पार्टी ओर सरकार का बचाव किया जा रहा है।

विकास खंड और जिले में कोई कमी नहीं गैस सिलेंडर की, किल्लत की खबरों से बुकिंग की बाढ़ से फैल रहा भ्रम

गैस की किल्लत की खबरों को लेकर भाजपा नेता जितेंद्र राठौर मंडल झकनावदा क्षेत्र से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि, देश में छोटे से लेकर बड़े शहरों की परिस्थितियां ओर मांग व पूर्ति की स्थितिया अलग-अलग है लेकिन हम, हमारे क्षेत्र ओर जिले की बात करे तो फिलहाल गैस सिलेंडर को लेकर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जिनकी बुकिंग हो गई है उनको उसी दर पर गैस एजेंसी से सिलेंडर आसानी से मिल रहा है। युद्ध जैसी गंभीर परिस्थितियों में उसी क्षेत्र से आने वाली आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान में परेशानी आना लाजमी है। रसोई गैस सहित अन्य ईंधन भी खाड़ी देशों से आते है जहां वर्तमान में युद्ध चल रहा है ,इसके बावजूद भी गैस सहित अन्य ईंधन पर्याप्त मात्रा में देश में है। अचानक आई गैस सिलेंडरो की कमी पर जितेन्द्र राठौर ने कहा कि, विपक्ष द्वारा गैस की किल्लत का भ्रम फैलाया गया जिससे लोगों में गैस बुकिंग की होड लग गई ओर अचानक आए बुकिंग के दबाओ के चलते गैस की किल्लत की बात उठने लगी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आज लोगों को बुकिंग के बाद तुरंत सिलेंडर मिल रहे है।

एजेंसियों पर भीड़ क्यों, घर पहुंच सुविधा हुई प्रभावित

मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर से पूछा गया कि, आखिर गैस की किल्लत नहीं है तो गैस एजेंसियों पर भीड़ क्यों है और घर पहुंच सेवा बंद क्यों है। तो राठौर ने बताया कि, ऐसा कुछ नहीं है, जिनको बुकिंग के दो-चार दिन में घर सिलेंडर मिल जाते थे वो सभी बुकिंग होते है सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी पर पहुंच रहे है। जिससे एजेंसियों पर भीड़ दिख रही है और यही वजह है कि, घर पहुंच सेवा प्रभावित हुई है। अगर लोगों में सिलेंडरों की कमी का बना माहौल खत्म हो जाए तो लोग बुकिंग के बाद अगर घर पर ही इंतजार करे तो घर पहुंच सेवा भी जल्द ही बहाल हो जाएगी। वैसे कई स्थानों पर अभी भी घर पहुंच सेवाएं जारी हैं।

जरूरी वस्तुओं के खर्च पर सबक लेने की आवश्यकता

मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर ने कहा कि, विश्व के कई देशों में युद्ध का भारी संकट छाया हुआ है ओर कई देश आपस में लड़ रहे। ऐसे में हमारा देश सुरक्षित नेतृत्व के साथ अपना सामान्य जीवन जी रहा है। विषम परिस्थितियों में देश कोरोना काल में भी उभर आया है और आज विश्व भर में भारत का नाम बढ़े लीडर के रूप में लिया जाता है। आज युद्ध की स्थिति हमारे आसपास के देशों मध्य एशिया में ही बनी हुई है जिससे देश की व्यवस्थाएं थोड़ी तो प्रभावित होगी ही। ऐसे में जरूरी चीजों के खर्च पर सबक लेने की आवश्यकता है ताकि हम लंबे समय तक किसी बड़ी समस्या से नहीं जूझे।

व्यवसायिक सिलेंडर नहीं होने से प्रभावित हुआ व्यापार

सरकार ने गैस सिलेंडरो की बुकिंग की अवधि 21 दिन से बड़ा कर 25 दिन कर दी। वही व्यवसायिक सिलेंडर के वितरण पर रोक लगा दी जिससे गैस आधारित छोटे से लेकर बड़ा व्यवसाय प्रभावित हुआ है। इस पर मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर ने कहा कि, ये सही है कि व्यवसायिक सिलेंडर नहीं मिलने से कई व्यवसाय प्रभावित हुए है, लेकिन भारत में हर परिस्थिति में उसके स्थान पर अन्य साधन के उपयोग से व्यवसाय करने की व्यवस्था मौजूद है और लोग उसका उपयोग कर अपना काम चला रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही व्यवसायिक सिलेंडरों की उपलब्धता भी हो जाएगी। कुल मिलाकर गूंज के सभी सवालों पर मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर ने बड़ी बेबाकी के साथ सरकार का बचाओ करते हुए विपक्ष को घेरा ओर अपनी बात इस गंभीर मुद्दे पर रखी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422